[2022] 8 एस.सी.आर. 349

जम्मू और कश्मीर राज्य

(अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और

कश्मीर) और अन्य

बनाम

शुबम सांगरा

(आपराधिक अपील संख्या 1928/2022) 16 नवंबर, 2022

[अजय रस्तोगी और जे.बी. पारदीवाला, न्यायाधीश.]

किशोर न्याय: जम्मू और कश्मीर किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2014: आर.74 - किशोर की दलील - कठुआ बलात्कार मामला - कठुआ बलात्कार मामले में छह पुरुषों द्वारा आठ साल की लड़की का अपहरण, सामूहिक बलात्कार और हत्या शामिल था और प्रतिवादी (किशोर होने का दावा) की - विशेष मेडिकल बोर्ड ने उम्र 19 वर्ष से अधिक बताई - हालांकि, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कठुआ ने बयान पर भरोसा किया। कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका समिति और प्रतिवादी के पिता के बयान में माना गया कि प्रतिवादी अपराध की तारीख पर किशोर था । उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा - इसलिए राज्य द्वारा त्वरित अपील को माना गया: आर.74 के उप नियम (3) में प्रावधान है कि उल्लिखित प्रमाणपत्रों की अनुपस्थिति में या किसी विरोधाभास की स्थिति में, उम्र के मुद्दे पर निर्णय लेने वाला प्राधिकारी मामले को विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड को संदर्भित कर सकता है । "हो सकता है" शब्द को "करेगा" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जो कि मूल उद्देश्य को ध्यान में रखता है। धारा 74 का उपनियम (3) - यदि किशोर आरोपी के पक्ष में स्पष्ट मामला है कि वह घटना की तारीख पर नाबालिग था और दस्तावेजी साक्ष्य कम से कम प्रथम दृष्टया इसे स्थापित करते हैं, तो वह किशोर न्याय अधिनियम के तहत विशेष सुरक्षा का हकदार होगा जबकि कोई आरोपी जघन्य और गंभीर अपराध करता है और उसके बाद नाबालिग होने की आड़ में वैधानिक आश्रय लेने का प्रयास करता है, तो यह दर्ज करते समय कि वह किशोर है या नहीं, एक आकस्मिक या लापरवाह दृष्टिकोण की अनुमति नहीं दी जा सकती है- पांच योग्य डॉक्टरों की एक टीम द्वारा दी गई अंतिम राय की विश्वसनीयता को नज़रअंदाज़ करने या अनदेखा करने या संदेह करने का कोई उचित कारण

नहीं है - अन्य सभी स्वीकार्य सामग्रियों की अनुपस्थिति में, यदि विशेषज्ञों की राय उसकी उम्र की सीमा के संबंध में उचित संभावना की ओर इशारा करती है, तो न्यायालय को न्याय के हित में उस पर विचार करना चाहिए - तत्काल मामले में, जन्म तिथि का सबूत देने वाले दस्तावेज़ किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करते थे और न्याय के हित में इसे गिराने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था।

विशेष मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर वापस आते हैं - मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की पुष्टि करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानून में टिकाऊ नहीं था - प्रतिवादी आरोपी अपराध के समय किशोर नहीं था और इसलिए, उस पर उसी तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए जिस तरह अन्य सह-अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया था - किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 - एस एस.7 ए और 94

- जम्मू और कश्मीर किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2013 - एस एस.8 और 48

जम्मू और कश्मीर किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2013: अनुभाग.8, 48 - अधिनियम, 2013 की धारा 8 को पढ़ने से संकेत मिलता है कि जब भी किसी के सामने किशोर होने का दावा उठाया जाता है या अदालत की राय है कि अपराध करने की तिथि पर आरोपी व्यक्ति किशोर था, तो अदालत के लिए जांच करना अनिवार्य है और ऐसी जांच के दौरान, अदालत ऐसे साक्ष्य ले सकती है जो आवश्यक हो सकते हैं, ताकि ऐसे व्यक्ति की उम्र निर्धारित की जा सके, हालांकि, शपथ पत्र लेने की जरुरत नहीं है ।

जांच के अंत में यदि अदालत किसी व्यक्ति को धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत अपराध करने की तिथि पर किशोर पाती है, तो ऐसी परिस्थिति में, अदालत उचित आदेश और सजा पारित करने के लिए किशोर को किशोर न्याय बोर्ड के पास भेजने के लिए कानूनन बाध्य है - धारा 48 एक सक्षम प्राधिकारी के बारे में बात करती है, जबकि, धारा 8 अदालत के संबंध में है - हालांकि, नोट के लिए जो प्रासंगिक है वह यह है कि दोनों धाराओं में शब्द 'करेगा' का प्रयोग किया गया है।

शब्द और वाक्यांश: "मे" - जब अनिवार्य - यह निर्वचन का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि 'मे' शब्द का प्रयोग विधान में अपने आप में एक निर्देशात्मक अर्थ नहीं दर्शाता है - यदि किसी विशेष मामले में, न्याय और समता के हित में, यह अदालत के लिए स्पष्ट हो कि विधायिका का उद्देश्य एक कानूनी कर्तव्य को व्यक्त करना है, तो 'मे' शब्द का प्रयोग अदालत को इसे

अनिवार्य रंग देने से नहीं रोक पाएगा - जम्मू और कश्मीर बाल न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2014 - नियम 74।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए

माना: 1. नियम 74 का उप-नियम (3), यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि उप खंड (i) से (iii) में उल्लिखित प्रमाणपत्रों की अनुपस्थिति में या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी विरोधाभास की स्थिति में, उम्र के मुद्दे पर निर्णय लेने वाला प्राधिकारी इस मामले को विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड को भेज सकता है, जो बदले में अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड और किशोर न्याय बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। प्रतिवादी की जन्मतिथि का खुलासा करने वाले रिकॉर्ड में प्रमाण पत्र में विसंगतियां हैं। ऐसा कोई अच्छा कारण नहीं है कि इस मामले को विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड को नहीं भेजा जाना चाहिए, जो बदले में अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड करेगा और किशोर न्याय बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। नियम 74 के उप-नियम (3) के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए "हो सकता है" शब्द को "करेगा" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। [पैरा 38] [380-एफ-जी; 381-ई.पू.]

2. अधिनियम, 2013 की धारा 8 को स्पष्ट रूप से पढ़ने से पता चलता है कि जब भी किसी अदालत के समक्ष किशोर होने का दावा किया जाता है या अदालत की राय है कि आरोपी व्यक्ति अपराध करने की तारीख पर किशोर था, तो अदालत के लिए जांच करना अनिवार्य है और ऐसी जांच के दौरान, अदालत ऐसे सबूत ले सकती है जो आवश्यक हो सकते हैं, हालांकि, कोई हलफनामा नहीं ले सकती है, ताकि ऐसे व्यक्ति की उम्र निर्धारित की जा सके। जांच के अंत में, यदि अदालत धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत अपराध करने की तिथि पर किसी व्यक्ति को किशोर पाती है, तो ऐसी परिस्थिति में, अदालत उचित आदेश और सजा पारित करने के लिए किशोर को किशोर न्याय बोर्ड के पास भेजने के लिए कानूनन बाध्य है। धारा 48 एक सक्षम प्राधिकारी के बारे में बात करती है, जबकि अधिनियम 2013 की धारा 8, न्यायालय के संबंध में है। हालाँकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों धाराओं यानी धारा 8 और साथ ही धारा 48 में 'करेगा' शब्द का इस्तेमाल किया गया है। [पैरा 42 और 44][383-बी-डी; 383-एच; 384-ए]

3. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि किशोर आरोपी के पक्ष में स्पष्ट मामला है कि वह घटना की तारीख पर नाबालिग था और दस्तावेजी सबूत कम से कम प्रथम दृष्टया इसे स्थापित करते हैं, तो वह किशोर न्याय अधिनियम के तहत विशेष सुरक्षा का हकदार होगा। हालाँकि,

जब कोई आरोपी किसी जघन्य और गंभीर अपराध को अंजाम देता है और उसके बाद नाबालिग होने की आड़ में वैधानिक आश्रय लेने का प्रयास करता है, तो यह दर्ज करते समय एक आकस्मिक या लापरवाह दृष्टिकोण की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि क्या आरोपी किशोर है या नहीं, क्योंकि अदालतों को न्याय प्रशासन के साथ सौंपी गई संस्था में एक आम आदमी के विश्वास की रक्षा करने के उद्देश्य से अपने कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। [पैरा 72][399-जी-एच; 400-ए]

4. ऐसा कोई अच्छा कारण नहीं है कि यह न्यायालय पांच योग्य डॉक्टरों की एक टीम, एक फिजियोलॉजी विभाग से, एक एनाटॉमी विभाग से, एक ओरल डायग्नोसिस विभाग से, एक डिपार्टमेंट ऑफ ओरल डायग्नोसिस से दी गई अंतिम राय की विश्वसनीयता को नजरअंदाज या अनदेखा या संदेह करे।

फोरेंसिक मेडिसिन और रेडियो डायग्नोसिस विभाग से, सभी एक शब्द में कह रहे हैं कि शारीरिक, दंत और रेडियोलॉजिकल परीक्षण के आधार पर, उत्तरदाता की अनुमानित आयु 19 से 23 वर्ष के बीच तय की जा सकती है। स्पेशल द्वारा तैयार मेडिकल रिपोर्ट की विश्वसनीयता के संबंध में प्रतिवादी अभियुक्त की ओर से ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है।

पांच चिकित्सा विशेषज्ञों से गठित विशेष चिकित्सा बोर्ड द्वारा तैयार की गई चिकित्सा रिपोर्ट की विश्वसनीयता के बारे में प्रतिवादी अभियुक्त के पक्ष में कुछ भी नहीं कहा गया है। एकमात्र तर्क यह है कि मेडिकल रिपोर्ट को नजरअंदाज करें क्योंकि रिकॉर्ड पर विभिन्न दस्तावेजों में जन्मतिथि का प्रमाण मौजूद है। जन्मतिथि को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज़ किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं और न्याय के हित में विशेष चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट पर भरोसा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।

[पैरा 74 और 77][400-जी; 401-एफ-जी]

बच्चन देवी बनाम नगर निगम, गोरखपुर (2008) 12 एससीसी 372: [2008] 2 एससीआर 424; ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। (2022) 8 एससीसी 602; पराग भाटी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2016) 12 एससीसी 744: [2016] 2 एससीआर 1089- आधृत किया गया.

रामदेव चौहान उर्फ राज नाथ बनाम असम राज्य (2001) 5 एससीसी 714: [2001] 3 एससीआर 669; अश्वनी कुमार सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2012) 9 एससीसी 750

: **[2012] 10 एससीआर 540**; दरगा राम उर्फ गूंगा बनाम राज्य

राजस्थान का (2015) 2 एससीसी 775: [2015] 1 एससीआर 350;

धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम यूपी राज्य। (2007) 8 एससीसी 338 : [2007] 10 एससीआर 245; मुकर्रब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2017) 2 एससीसी 210: [2016] 8 एससीआर 557; संजीव कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2019) 12 एससीसी 370: [2019] 9 एससीआर 735; अबुजर हुसैन @ गुलाम हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2012) 10 एससीसी 489: [2012] 9 एससीआर 244; अश्वनी कुमार सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2012) 9 एससीसी 750: [2012]

10 एससीआर 540; बब्लू पासी बनाम झारखंड राज्य, (2008) 13 एससीसी 133: [2008] 14 एससीआर 161; अर्निंत दास बनाम राज्य और कश्मीर) बनाम शुबम सांगरा

<u>केस कानून संदर्भ</u> पैरा 32

[2001] 3 एससीआर 669	संदर्भित	पैरा 35
[2012] 10 एससीआर 540	संदर्भित	पैरा 39
[2015] 1 एससीआर 350	संदर्भित	पैरा 40
[2008] 2 एससीआर 424	संदर्भित	पैरा 47
[2007] 10 एससीआर 245	संदर्भित	पैरा 58
[2016] 8 एससीआर 557 (2022) 8 एससीसी 602		संदर्भित पैरा 58 (i)
[2016] 2 एससीआर 1089	संदर्भित	पैरा 58 (ii)
[2019] 9 एससीआर 735	संदर्भित	पैरा 58 (iii)
[2012] 9 एससीआर 244	संदर्भित	पैरा 58 (iv)
[2012] 10 एससीआर 540	संदर्भित	पैरा 59 (v)
[2008] 14 एससीआर 161		
[2000] 1 पूरक एससीआर 69	संदर्भित	पैरा 58 (vi)
[2006] 1 पूरक। एससीआर 286	संदर्भित	पैरा 58 (vii)

[2012] 5 एससीआर 237 संदर्भित पैरा 70

बिहार का, (2000) 5 एससीसी 488: [2000] 1 पूरक। एससीआर 69; जितेंद्र राम उर्फ जीतू बनाम झारखंड राज्य, (2006) 9 एससीसी 428: [2006] 1 पूरक। एससीआर 286; ओम प्रकाश बनाम राजस्थान राज्य (2012) 5 एससीसी 201: [2012]5 एससीआर 237- संदर्भित

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2022 की आपराधिक अपील संख्या 1928।

2018 के सीआरआर संख्या 27 में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 11.10.2019 से।

पी. एस. पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, शैलेश मडियाल, पार्थ अवस्थी, वैभव सभरवाल, विनायक एस. पंडित, सुश्री हर्षिका वर्मा, सुश्री तरूणा अर्धेन्दुमौली प्रसाद, अधिवक्ता। अपीलकर्ताओं के लिए.

नितिन सांगरा, श्रीमती प्रज्ञा बघेल, सलाहकार। प्रतिवादी के लिए.

न्यायालय का निर्णय

जे बी. पारदीवाला, न्यायाधीश

द्वारा सुनाया गया।

"बलात्कार पृथ्वी पर सबसे भयानक अपराधों में से एक है और यह हर कुछ मिनटों में होता है। बलात्कार से निपटने वाले समूहों के साथ समस्या यह है कि वे महिलाओं को बचाव के तरीके के बारे में शिक्षित करने का प्रयास करते हैं।

वास्तव में जो करने की ज़रूरत है वह पुरुषों को बलात्कार न करने की शिक्षा देना है। स्रोत पर जाएं और वहां से शुरुआत करें।"

- कर्ट कोबेन

1. यह अपील जम्मू और कश्मीर राज्य के अनुरोध पर है

(अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर) और जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.10.2019 को पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता राज्य द्वारा दायर 2018 के आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन संख्या 27 को खारिज कर दिया, जिससे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कठुआ द्वारा 27.03.2018 को पारित आदेश की

पुष्टि हुई, जिसमें प्रतिवादी आरोपी कथित अपराध के कमीशन की तारीख को किशोर माना गया था।

2. यह मुक़दमा सबसे दुर्भाग्यपूर्ण कठुआ बलात्कार मामले से उत्पन्न हुआ है। कठुआ बलात्कार मामले में जनवरी, 2018 में छह हिंदू पुरुषों और प्रतिवादी (किशोर होने का दावा करते हुए) द्वारा जम्मू-कश्मीर में कठुआ के पास रसाना गांव में 'एक्स' नाम की आठ वर्षीय मुस्लिम लड़की का अपहरण, सामूहिक बलात्कार और हत्या शामिल थी।

पीड़िता खानाबदोश बकरवाल समुदाय से थी. वह एक सप्ताह तक गायब रही और ग्रामीणों ने उसका शव गांव से एक किलोमीटर दूर बरामद किया। इस भयानक अपराध के संबंध में कुल मिलाकर आठ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें यहां प्रतिवादी भी शामिल है। चूँकि यहाँ प्रतिवादी ने किशोर होने का दावा किया, उसका मुकदमा अलग कर दिया गया। अन्य छह सह- अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 10.06.2019 के अनुसार, सात आरोपियों में से छह को दोषी ठहराया गया और एक आरोपी को बरी कर दिया गया। दोषियों में से तीन को आजीवन कारावास और शेष तीन को पाँच वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई। पूरे मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया और अंततः सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। पीड़िता के पिता 'वाई' ने हीरा नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी लापता हो गई है।

3. 17.01.2018 को पीड़िता का शव मिला और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम उसी दिन जिला अस्पताल, कठुआ में डॉक्टरों की एक टीम द्वारा परीक्षण किया गया। 22.01.2018 को मामले की जांच अपराध शाखा एवं अपराध मुख्यालय को स्थानांतरित कर दी गई।

5. दिल्ली फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने सबूतों के चौदह पैकेटों का विश्लेषण किया जिसमें योनि के स्वाब, बालों के टुकड़े, चार आरोपियों के रक्त के नमूने, मृत लड़की का विसरा, लड़की की फ्रॉक और सलवार, साधारण मिट्टी और खून से सनी मिट्टी शामिल थी। कुछ अन्य नमूनों की तरह योनि स्वैब का आरोपी के डीएनए से मिलान हुआ। मंदिर में, जहां मृतक के साथ बलात्कार किया गया था, वहां पाए गए बालों की लटें लड़की और आरोपी के बालों से मेल खाती हैं।

6. आरोपी व्यक्तियों में से एक सांजी राम और उसके प्रतिवादी को मामले में मुख्य आरोपी पाया गया। वह प्रासंगिक समय पर उस पारिवारिक मंदिर का पुजारी था जहां कथित तौर पर घटना हुई थी। यहां प्रतिवादी सांजी राम का भतीजा है।

7. 10.06.2019 को सात आरोपियों में से छह को दोषी पाया गया और एक को बरी कर दिया गया। सांजी राम, दीपक खजूरिया और परवेश कुमार को 25-25 साल की उम्रकैद और 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। एक-एक लाख अन्य तीन आरोपियों तिलक राज, आनंद दत्ता और सुरिंदर कुमार को मामले में महत्वपूर्ण सबूत नष्ट करने के लिए पांच साल जेल की सजा सुनाई गई थी। विशाल जंगोत्रा पुत्र सांजी राम को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। आठवां आरोपी, जिस पर अपराध के समय किशोर होने का दावा करते हुए मुकदमा चलाया जाना बाकी है, यहां प्रतिवादी है।

8. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ रखा गया विशिष्ट मामला आरोपपत्र में

इस प्रकार निहित है:

"...वह तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरा, 3 मनार और चाबियाँ लेकर देवीस्थान गया और 'एक्स' को बताया कि उसने उसके घोड़े देखे हैं।

वह उसे जंगल की ओर ले गया और आरोपी मन्नू को भी बुलाया जो पहले से ही उसके संकेत का इंतजार कर रहा था। किसी परेशानी को भांपकर पीड़िता ने वहां से भागने की कोशिश की। जेडी ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे रोका और अपने एक हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया और उसे धक्का दिया और वह जमीन पर गिर गई। आरोपी मन्नू ने उसके पैर पकड़ लिए और जेसीएल (प्रतिवादी) ने उसे मनार दिया, एक-एक करके पीड़िता से जबरदस्ती की। पीड़िता बेहोश हो गई और जेसीएल द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया... बाद में, वे लड़की को ले गए और उसे देवीस्थान के अंदर टेबल के नीचे दो चटाई (प्लास्टिक की चटाई) के ऊपर रखा और फिर उसे दो डेरियों (सूती धागे की चटाई) से ढक दिया...

सुबह लगभग 8.30 बजे जेसीएल फिर से देवीस्थान गया और लड़की को 3 शामक गोलियां दीं, जबकि वह खाली पेट बेहोश थी....

...आरोपी विशाल जंगोत्रा उर्फ शम्मा ने 'एक्स' के साथ बलात्कार किया।

इसके बाद जेसीएल ने भी आरोपी की मौजूदगी में लड़की के साथ बलात्कार किया

जांच में यह भी पता चला कि बलात्कार करने के बाद जेसीएल ने आरोपी विशाल जंगोत्रा उर्फ शम्मा और आरोपी मन्नू को देवीस्थान छोड़ने का निर्देश दिया। जेसीएल ने फिर देवीस्थान के बाहर बिजली के खंभे के पास कूड़े के ढेर के नीचे रखी पट्टी से 03 गोलियां निकालीं और दीं

लड़की के साथ भी ऐसा ही किया और उसे छुपाने के लिए फिर से यहां चटाई से ढक दिया और उसके सामने बर्तन का डिब्बा गिरा दिया...

जांच में पता चला है कि लोहड़ी वितरण के बाद

शाम को रिश्तेदारों को की जानकारी जेसीएल ने आरोपी सांजी राम को दी

कि उसने और आरोपी विशाल जंगोत्रा ने देव स्थान के अंदर 'एक्स' के साथ सामूहिक बलात्कार किया था... मौके पर आरोपी दीपक खजुरिया उर्फ दीपू ने जेसीएल से कहा कि वह इंतजार करे क्योंकि वह लड़की को मारने से पहले उसके साथ बलात्कार करना चाहता था। ऐसे में एक बार फिर छोटी बच्ची 'एक्स' के साथ पहले आरोपी दीपल खजूरिया उर्फ दीपू और फिर जेसीएल ने सामूहिक बलात्कार किया। उसके बायीं जांघ पर बलात्कार की बर्बरतापूर्ण वारदात को अंजाम देने के बाद उसे जान से मारने के लिए उसकी गर्दन पर अपने हाथों से जोर लगाना शुरू कर दिया. चूंकि आरोपी दीपक खजुरिया उर्फ दीपू उसे मारने में असफल रहा था, दूसरे आरोपी जेसीके ने उसकी पीठ पर अपने घुटने दबाकर उसकी हत्या कर दी और चुन्नी के दोनों सिरों पर बल लगाकर लड़की का गला घोंट दिया।

इसके बाद, आरोपी जेसीएल ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीड़िता मर गई है, उसके सिर पर पत्थर से दो बार वार किया...

... योजना अनुसार जेसीएल आरोपी विशाल जंगोत्रा उर्फ शम्मा के साथ देवीस्थान गया। आरोपी विशाल जंगोत्रा उर्फ शम्मा ने दरवाजा खोला जबकि जेसीएल ने शव को अपने कंधे पर उठाया। आरोपी विशाल जंगोत्रा उर्फ शम्मा ने दरवाजा बंद कर दिया और जेसीएल ने शव को जंगल के अंदर फेंककर ठिकाने लगा दिया, जबकि आरोपी विशाल जंगोत्रा उर्फ शम्मा बाहर झाड़ियों की रखवाली कर रही था..."

इसके अलावा, दिनांक 09-08-2018 के पूरक आरोप पत्र में इसे निम्नानुसार देखा गया है: -

... "जांच के दौरान, यह पहले ही स्थापित हो चुका है कि पीड़िता को कैद के दौरान आरोपियों द्वारा शामक दवाएं दी गई थीं। देवस्थान रसना के पास कानून के साथ संघर्ष कर रहे किशोर के खुलासे पर बरामद की गई दो गोलियों को विश्लेषण के लिए फोरेंसिक प्रयोगशाला में भेजा

गया था। प्राप्त रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट से उक्त गोलियों में क्लोनाज़ेपम नमक मौजूद होने का पता चला। खाली पेट पीड़ित पर शामक 'मन्नार' के साथ-साथ क्लोनाज़ेपम के प्रभाव का पता लगाने के लिए, संबंधित विशेषज्ञ ने कहा। (प्रोफेसर और प्रमुख, फार्माकोलॉजी, जीएमसी जम्मू) ने राय दी है कि शामक क्लोनाज़ेपम (एपिट्रिल 0.एसएमजी) के निम्नलिखित प्रभाव हैं: - (1) उनींदापन, (2) भ्रम, (3) बिगड़ा हुआ, (4) समन्वय, (5) धीमी प्रतिक्रिया, (6) धीमी या बंद सांस, (7) कोमा (चेतना की हानि) और मृत्यु। विशेषज्ञ की अंतिम राय के अनुसार, "क्लोनाज़ेपम की अधिकतम सांद्रता मौखिक सेवन के एक से डेढ़ घंटे बाद रक्त में प्राप्त होती है।"आंत्र मार्ग से क्लोनाज़ेपम का अवशोषण पूर्ण होता है, चाहे इसे भोजन के साथ या बिना भोजन के दिया जाए। ..."

9. यहां प्रतिवादी पर जिस अपराध का आरोप लगाया गया है वह जघन्य है; इसका क्रियान्वयन किसी भी दृष्टि से क्रूर था। सारा अपराध सुविचारित और निर्मम था। इस मामले ने देश भर में, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य में समाज का ध्यान एक क्रूर अपराध के रूप में आक्रोश आकर्षित किया, जिसने समुदाय के भीतर सुरक्षा के बारे में चिंता पैदा कर दी।

10. वर्तमान मुकदमे में हमारा निर्णय इस प्रश्न तक ही सीमित है कि क्या अपराध करने की तिथि पर प्रतिवादी किशोर था? यह सब जम्मू उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 21.02.2018 के आदेश से शुरू हुआ:

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दिनांक 19.02.2018 की स्थिति रिपोर्ट का भाग दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है,

अर्थात् ग्रेटर कश्मीर, विस्तार में और मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए और साथ ही स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए, मैं यह निर्देश देना उचित समझता हूं कि तत्काल रिट याचिका की कार्यवाही किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं की जाएगी।

09.03.2018 की सूची सबसे नीचे सूची में ।

11. उच्च न्यायालय द्वारा ऊपर उल्लिखित आदेश में जारी निर्देशों के अनुपालन में, विशेष जांच दल ने अपने पत्र दिनांक 26.02.2018 के माध्यम से प्रिंसिपल, सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू से प्रतिवादी की आयु के निर्धारण के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का अनुरोध किया।

12. सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू के प्रिंसिपल और डीन ने निम्नलिखित डॉक्टरों को शामिल करते हुए एक विशेष मेडिकल बोर्ड का गठन किया:

क्रम संख्या	**नाम**	**पद**
1	*डॉ मृत्युंजय*	*प्राध्यापक, शरीर क्रिया क्रिज्ञान क्रिभाग*
2	*डॉ अश्वनी*	*सहायक प्राध्यापक, शरीर रचना निदान क्रिभाग*
3	*डॉ सत्यविंदर सिंह*	*व्याख्याता, मौखिक निदान विभाग , आईजीजीडीसी, जम्मू*
4	*डॉ शिवानी मेहता*	*व्याख्याता, फोरेंसिक मेडिसिन विभाग*
5	*डॉ जीवितेश खुदा*	*रेजिस्ट्रार, रेडियो निदान विभाग*

13. उपर्युक्त विधि से गठित विशेष चिकित्सा बोर्ड ने प्रतिवादी की चिकित्सा जांच की और दिनांक 03.03.2018 को अपनी रिपोर्ट दी, जो इस प्रकार है:

<u>आयु अनुमान रिपोर्ट</u>

नाम: शुभम सांगरा उर्फ शुबू लिंग: पुरुष

पिता: श्री ओम प्रकाश सांगरा

पता: हीरा नगर, वार्ड संख्या 10, एनपी रसाना

व्यक्ति द्वारा बताई गई आयु/ विविध डेटा: 15 वर्ष

पेश करने वाला/प्राधिकरण: उप एसपी श्वेतांबर शर्मा

स्थायी चिकित्सा बोर्ड, संख्या: जीएमसी/2018/एसएमबीडी केपीएस - 125747 न्यायालय मामला संख्या: 12176 दिनांक: 26/02/2016 अपराध शाखा, जम्मू।

परीक्षा का उद्देश्य: शुभम संगरा की आयु का आकलन

हस्ताक्षर/-

(व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

पहचान चिह्न: 1. मुँह के बाएँ कोने के ऊपर काला तिल

2. दाहिनी भौं पर निशान

1. शारीरिक परीक्षण

(i) ऊँचाई 5’3" (ii) वजन 48 किलोग्राम

(ii) औसत कद-काठी (iii) मर्दाना आवाज

(v) द्वितीयक यौन लक्षण सुविकसित

II. दंत परीक्षण

दाहिना ऊपरी दांत 87654321	दाहिना ऊपरी दांत 12345678
87654321 निचले जबड़े का दाहिना हिस्सा	12345678 निचले जबड़े का दाहिना हिस्सा

डॉ. सतविंदर सिंह द्वारा दंत आयु निर्धारण हेतु आईजीजीडीसी जम्मू के मुख निदान विभाग को भेजा गया।

03/03/2018 - नैदानिक परीक्षण में, 18, 28, 38 और 48 को छोड़कर सभी स्थायी दांत निकल आए थे। ओपीजी (रेडियोग्राफिक) परीक्षण में 18 और 28 में लगभग वी2 रूट फॉर्मेशन दिखाई दिया।

38 और 48 में लगभग पूर्ण रूट फॉर्मेशन के साथ खुला (अस्पष्ट) भाग दिखाई दिया। इन निष्कर्षों के आधार पर, रोगी की दंत आयु 19 वर्ष से अधिक है।

III. रेडियोलॉजिकल परीक्षण: आयु निर्धारण हेतु एक्स-रे के लिए रेडियो निदान विभाग को भेजा गया।

सलाह दी गई (1) एक्स-रे (दायां) ह्यूमरस (कंधे का जोड़) एपी (2) एक्स-रे हिप (पेल्विस) एपी (3) एक्स-रे (आरएफ) घुटने का जोड़-एपी (4) एक्स-रे (दायां) कोहनी का जोड़ एपी पार्श्व (5) एक्स-रे (दायां) हाथ और कलाई- एपी।

राय - आईजीजीडीसी एफ जम्मू और रेडियो डायग्नोसिस विभाग से रिपोर्ट प्राप्त होने तक सुरक्षित।

हस्ताक्षरित/- हस्ताक्षरित

डॉ मृत्युंजय शिवानी मेहता

(फिजियोलॉजी विभाग) (फोरेंसिक मेडिसिन विभाग)

हस्ताक्षरित/- हस्ताक्षरित/- हस्ताक्षरित/-

डॉ. जीवितेश खुदा डॉ. अश्वनी डॉ. सतविंदर

(रेडियो विभाग (एनाटॉमी विभाग) (आईजीडीडीसी जम्मू)

निदान)

3/03/2018 अंतिम राय - डॉ. जीवतेश खोड़ा द्वारा रिपोर्ट की गई आर/8" x 10" x चार (4) फिल्मों के आधार पर, उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में रोगी की आयु उन्नीस से तेईस (19-23) वर्ष के बीच है।

14. इसके बाद उच्च न्यायालय ने दिनांक 14.03.2018 को ओडब्ल्यूपी संख्या 259/2018 और एम.पी. संख्या 1/2018 में एक आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया है:

"आज जब इस मामले की सुनवाई हुई, तो माननीय वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि जिला अस्पताल कठुआ के चिकित्सा अधीक्षक से अनुरोध किए जाने के बावजूद, आज तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जांच अधिकारी को नहीं सौंपी गई है। उपरोक्त निवेदन के मद्देनजर, जिला अस्पताल कठुआ के चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि वे आज पारित आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन दिनों के भीतर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति और प्रश्नावली के उत्तर विशेष जांच दल के प्रमुख अधिकारी को सौंप दें।"

प्रतिवादी 1 से 3 की ओर से दायर की गई स्थिति रिपोर्ट के पैरा 7 में उल्लिखित कथनों के संबंध में, यह निवेदन किया जाता है कि विशेष जांच दल फरार आरोपी संझी राम के लिए गिरफ्तारी वारंट प्राप्त करे और उसे गिरफ्तार करने के लिए सभी प्रभावी कदम उठाए तथा उससे तथा उन अन्य व्यक्तियों से पूछताछ करे जिनका नाम स्थिति रिपोर्ट के पैरा 7 में उल्लिखित है और जो संबंधित अपराधों से जुड़े हैं। उपरोक्त प्रक्रिया आज से तीन सप्ताह के भीतर पूरी की जाए।

श्री नरगल, वरिष्ठ न्यायिक अटॉर्नी जनरल ने आगे निवेदन किया कि चूंकि मामला इस न्यायालय के समक्ष लंबित है, इसलिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कठुआ, अभियुक्त शुभम सांगरा की आयु का पता नहीं लगा रहे हैं।

उपरोक्त निवेदनों के मद्देनजर और जम्मू एवं कश्मीर किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2013 की धारा 8 तथा इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियमों के नियम 74 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कठुआ को निर्देश दिया जाता है कि

आज पारित आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से दस दिनों के भीतर अभियुक्त शुभम सांगरा की आयु का पता लगाएं, जिला चिकित्सा बोर्ड को प्रस्तुत रिपोर्ट से प्रभावित हुए बिना।

अध्ययन की सुनवाई 09.04.2018 को सूचीबद्ध करें।

इस आदेश की एक प्रति न्यायालय के पीठ सचिव की मुहर और हस्ताक्षर के साथ पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को उपलब्ध कराई जाए।

15. हीरा नगर के तहसीलदार ने अपने पत्र दिनांक

14.03.2018 के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, प्रभारी एसआईटी क्राइम ब्रांच को सूचित किया कि प्रतिवादी की जन्मतिथि से संबंधित मूल अभिलेख नहीं मिल पा रहा है। तहसीलदार का दिनांक 14.03.2018 का पत्र इस प्रकार है:

जम्मू एवं कश्मीर सरकार, राजस्व विभाग

तहसीलदार, कार्यवाहक मजिस्ट्रेट का कार्यालय

प्रथम श्रेणी, हीरानगर (कठुआ)

पुलिस उपाधीक्षक, एसआईटी सदस्य, अपराध शाखा, जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू।

संख्या जेसी/232, दिनांक: 14.03.2018

विषय: हीरानगर थाना क्षेत्र की एफआईआर संख्या 10/2018 धारा 363/302/343/376/201/120- बी आरपीसी की जांच।

संदर्भ: सीबी/एफआईआर/10- 2018/127 दिनांक 13.03.2018

माननीय महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में आपके कार्यालय के पत्र संख्या सीबी/एफआईआर/10-2018/127 दिनांक 13.03.2018 के संदर्भ में।

इस संदर्भ में यह निवेदन किया जाता है कि दिनांक 15.04.2004 को जारी आदेश संख्या 22/जेसी से संबंधित मूल अभिलेख उपलब्ध हैं।

शुभम संगरा पुत्र ओम प्रकाश निवासी हीरानगर की जन्मतिथि इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, पुराना विविध अभिलेख क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसके मूल अभिलेख प्रस्तुत करने में अधोहस्ताक्षरी सक्षम है।

भवदीय,

हस्ताक्षर/-

गौरव शर्मा,

तहसीलदार, हीरानगर

16. हीरा नगर के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ने दिनांक 15.03.2018 के अपने पत्र द्वारा जम्मू एवं कश्मीर की अपराध शाखा के प्रभारी पुलिस अधीक्षक को सूचित किया कि संस्था में उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन से पता चलता है कि प्रतिवादी की माता श्रीमती तृप्ता देवी पत्नी ओम प्रकाश के नाम से 23.10.2002 को कोई प्रसव नहीं हुआ था।

18. 23.02.2002 की तिथि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रतिवादी का कहना अपीलकर्ता राज्य ने धारा 8 के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर उपरोक्त आवेदन पर विस्तृत आपत्तियां दाखिल कीं। आपत्तियां इस प्रकार हैं:

क. 12.01.2018 को मोहम्मद यूसुफ पुत्र साहिब दीन जाति बकरवाल निवासी रसाना मोहरा प्लाख फवारा तहसील हीरानगर ने थाना हीरानगर में उर्दू में एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी बेटी सुश्री आसिफा, उम्र 8 वर्ष, का जन्म 23.10.2002 को हुआ था।

10.01.2018 को पास के जंगल में वह घोड़े चराने गई थी। उसे लगभग 14:00 बजे घोड़ों के साथ देखा गया था। लगभग 16:00 बजे घोड़े डेरा में वापस आ गए, लेकिन आसिफा नहीं लौटी। इस पर मोहम्मद यूसुफ ने अन्य लोगों के साथ जंगल में खोज शुरू की, लेकिन आसिफा

का पता नहीं चल सका। उन्हें संदेह है कि कुछ बदमाशों ने उनकी बेटी का अपहरण कर लिया है। परिणामस्वरूप, मामला एफआईआर संख्या 10/ 2018 धारा 363 के तहत दर्ज की गई। आरपीसी का पंजीकरण हीरानगर पुलिस स्टेशन में हुआ था और पीड़िता का शव बरामद होने के बाद धारा 302 और 343 भारतीय दंड संहिता जोड़ी गईं। थाना हीरानगर के जांच अधिकारी ने गुप्त सूचना के आधार पर शुभम संगरा उर्फ चुबू नामक एक किशोर अपराधी को 19.01.2018 को गिरफ्तार किया और उसे रिमांड के लिए 20.01.2018 को कठुआ के माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। इसके बाद मामले की जांच आगे की जांच के लिए पुलिस मुख्यालय आदेश संख्या 374/2018 दिनांक 22.01.2018 के तहत क्राइम ब्रांच जम्मू को स्थानांतरित कर दी गई। मामला औपचारिक रूप से 27.01.2018 को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। जांच के दौरान धारा 376, 201 और 120- बी भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध शामिल किए गए।

ख. कठुआ के माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शुभम संगरा उर्फ चुबू को आर.एस. पुरा स्थित अवलोकन गृह में रखने के लिए रिमांड मंजूर कर दी है, जिसका विवरण इस प्रकार है:-

ई. i. 20.01.2018 से 29.01.2018 = 10 दिन

ii. 29.01.2018 से 03.02.2018 = 6 दिन

iii.03.02.2018 से 12.03.2018 = 10 दिन

iv.12.02.2018 से 26.02.2018 = 15 दिन

एफ. v. 26.02.2018 से 12.03.2018 = 15 दिन

vi. 12.03.2018 से 22.03.2018 = 11 दिन

कुल - 67 दिन, (कैलेंडर प्रविष्टियों के अनुसार 62 दिन)

इसके अलावा, माननीय कठुआ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने दिनांक 30.01.2018, 05.02.2018, 19.02.2018 और 26.02.2018 के आदेशों के माध्यम से किशोर अपराधी शुभम संगरा को क्रमशः 3 दिन + 3 दिन + 3 दिन + 1 दिन की पुलिस हिरासत में रखा है। इस प्रकार, जांच के उद्देश्य से किशोर को कुल 10 दिनों की पुलिस हिरासत दी गई। पूछताछ के दौरान किशोर अपराधी ने मृतक आसिफा के अपहरण, बलात्कार और हत्या के अपराध स्वीकार

किए। घटनाक्रम में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और 164- ए के तहत गवाहों के बयान और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर, शुभम संगरा उर्फ चुबू के खिलाफ धारा 363, 343, 302, 376 और 120-बी के तहत प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध हुए हैं।

ग. इसके अलावा, जांच के दौरान यह भी पता चला कि किशोर का जन्म प्रमाण पत्र, जो हीरानगर नगर समिति से प्राप्त किया गया था, और हीरानगर के आधुनिक सार्वजनिक उच्च माध्यमिक विद्यालय से प्राप्त किया गया था, भिन्न थे। इसी बीच, माननीय उच्च न्यायालय ने 21.02.2018 को ओएचपी संख्या 259/2018 में मोहम्मद अख्तर बनाम राज्य के मामले में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित निर्देश पारित किए:-

"एसआईटी आज से 10 दिनों के भीतर शुभम

सांगरा की आयु का निर्धारण करने के लिए एक चिकित्सा बोर्ड गठित करेगी, जिसका गठन प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू द्वारा किया जाएगा।"

माननीय उच्च न्यायालय जम्मू के उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में, प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू को इस कार्यालय के पत्र संख्या सीबीजे/एफआईआर/10 2018/56 दिनांक 26.02.2018 के माध्यम से किशोर अपराधी शुभम सांगरा उर्फ चुबू की आयु निर्धारण के लिए एक चिकित्सा बोर्ड गठित करने का अनुरोध किया गया था। इसके जवाब में, प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू ने चिकित्सकों का एक बोर्ड गठित किया जिसमें (i) डॉ. मृत्युंजय, शरीर क्रिया विज्ञान विभाग (ii) डॉ. शिवानी मेहता, फोरेंसिक मेडिसिन विभाग (iii) डॉ. जीवतेश ख्तिदा, रेडियो डायग्नोसिस विभाग (iv) डॉ. अश्वनी, शरीर रचना विज्ञान विभाग और (v) डॉ. सतविंदर सिंह, इंदिरा गांधी सरकारी दंत महाविद्यालय जम्मू (आईजीजीडीसी) विभाग शामिल थे। इस प्रकार गठित चिकित्सकों के बोर्ड ने 28.02.2018 को किशोर अपराधी शुभम सांगरा की जांच की और तदनुसार प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू ने पत्र संख्या जीएमसी/2017/एसएमवीसी/कोर्ट केस/2209 दिनांक 05.03.2018 के माध्यम से बोर्ड की राय प्रस्तुत की।

अंतिम राय:-

शारीरिक, दंत और रेडियोलॉजिकल परीक्षण के आधार पर उपर्युक्त व्यक्ति की अनुमानित आयु उन्नीस वर्ष (19+) से अधिक है। (चिकित्सा रिपोर्ट की प्रति संदर्भ के लिए अनुलग्नक क के रूप में संलग्न है)।

घ. किशोर अपराधी शुभम सांगरा से पूछताछ, धारा 161 और 164-ए के तहत गवाहों के बयान

सीआरपीसी और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर, आरोपी व्यक्तियों बी (i) दीपक खजूरिया उर्फ दीपू पुत्र उपदेश खजूरिया (ii) सुरिंदर कुमार पुत्र सैन दास निवासी धामियाल हीरानगर और (iii) परवेश कुमार उर्फ मन्नू पुत्र अशोक कुमार निवासी रसाना हीरानगर, (iv) विशाल जांगोत्रा उर्फ शम्मा और (v) संजी राम को गिरफ्तार कर उनसे निरंतर पूछताछ की गई। अब तक की जांच से पता चलता है कि आरोपी दीपक कुमार खजूरिया और किशोर अपराधी ने संजी राम पुत्र देश राज निवासी रसाना के साथ मिलकर मृतक आसिफा, पुत्री मोहम्मद यूसुफ, रसाना निवासी के अपहरण, बलात्कार और हत्या की आपराधिक साजिश रची। इस आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाने के लिए आरोपी सुरिंदर कुमार पुत्र सैन दास निवासी धामियाल हीरानगर, परवेश कुमार उर्फ मन्नू पुत्र अशोक कुमार निवासी रसाना हीरानगर और विशाल जांगोत्रा उर्फ शम्मा भी साजिश और उसके क्रियान्वयन की योजना में शामिल हुए।

इसके अलावा, जांच के दौरान यह भी पता चला है कि हीरानगर थाने के अधिकारी और कर्मचारी आपराधिक साजिश में शामिल थे, क्योंकि मृतक आसिफा के कपड़े 17.01.2018 को फोरेंसिक जांच के लिए एफएसएल भेजे जाने से पहले हीरानगर पुलिस स्टेशन परिसर में धोए गए थे। आरोपियों के इकबालिया बयानों और गवाहों के बयानों (धारा 161 सीआरपीसी) के साथ-साथ अन्य परिस्थितियों के आधार पर, हीरानगर थाने के मुख्य जांच अधिकारी तिलक राज और हीरानगर थाने के इस मामले के पूर्व जांच अधिकारी आनंद दत्ता को, अपराधी को कानूनी सजा से बचाने के इरादे से सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दोनों पुलिस अधिकारी पुलिस हिरासत में हैं और जम्मू पुलिस शाखा में बंद हैं।

च. चिकित्सकों के बोर्ड की राय के अनुसार शुभम संगरा उर्फ चुबू की आयु उन्नीस वर्ष से अधिक है और इस प्रकार वह बालिग है। इसके अतिरिक्त यह निवेदन किया जाता है कि जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू में विचाराधीन याचिका संख्या 259/2018 (मोहम्मद अख्तर बनाम राज्य) में जीएमसी जम्मू के चिकित्सकों के बोर्ड की राय को दर्शाने वाली एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट माननीय न्यायालय के अवलोकन हेतु 09.03.2018 को सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई थी।

2. इस माननीय न्यायालय के समक्ष यह भी निवेदन करना प्रासंगिक है कि तहसीलदार हीरानगर को कार्यालय पत्र संख्या सीबी/एफआईआर/10-20181127 दिनांक 13.03.2018 के माध्यम से अनुरोध किया गया था कि नगर समिति हीरानगर के कार्यकारी अधिकारी को शुभम संगरा की जन्मतिथि नगर समिति के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी करने संबंधी फाइल उपलब्ध कराई जाए। उपरोक्त पत्र के जवाब में, तहसीलदार हीरानगर ने पत्र संख्या

जेसी/232 दिनांक 14.03.2018 के माध्यम से सूचित किया है कि संबंधित फाइल उनके कार्यालय में नहीं मिल रही है।(तहसीलदार का उत्तर संदर्भ के लिए संलग्न है और अनुलग्नक-बी के रूप में चिह्नित है)।

3. इसके अलावा यह भी निवेदन किया जाता है कि हीरानगर नगर समिति के कार्यकारी अधिकारी ने नगर समिति के जन्म रजिस्टर में नाबालिग शुभम सांगरा के संबंध में प्रविष्टि की है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त व्यक्ति का जन्म हीरानगर अस्पताल में हुआ था। हालांकि, इसके विपरीत, इस कार्यालय के पत्र संख्या सीबी/एफआईआर//10-2018/135 दिनांक 14.03.2018 के उत्तर में, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण हीरानगर ने कार्यालय पत्र संख्या सीबी/एफआईआर/ लेखाकार/2214 दिनांक 15.03.2018 के माध्यम से सूचित किया है कि संस्था में उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन पर यह पाया गया है कि श्रीमती त्रिपाता देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश निवासी हीरानगर,के नाम से 23.10.2002 को कोई प्रसव दर्ज नहीं है,जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि हीरानगर नगर समिति के कार्यकारी अधिकारी द्वारा की गई प्रविष्टि तथ्यों पर आधारित नहीं है और उक्त प्रविष्टि करने के लिए तहसीलदार हीरानगर का आदेश भी संदिग्ध हो गया है। (संदर्भ के लिए हीरानगर नगर निगम अधिकारी के पत्र की फोटोकॉपी संलग्न है और इसे अनुलग्नक- सी के रूप में चिह्नित किया गया है)।

4. यह भी रिकॉर्ड पर दर्ज करना प्रासंगिक है कि उपर्युक्त रिट याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष 14.03.2018 को सूचीबद्ध की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने सीलबंद लिफाफे में दाखिल स्थिति रिपोर्ट पर विचार करने के बाद तीन निर्देश जारी किए थे, जिनमें से वर्तमान मामले से संबंधित निर्देश संदर्भ के लिए नीचे दिया गया है:-

"जम्मू और कश्मीर किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2013 की धारा 8 और अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के नियम 74 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कठुआ को निर्देश दिया जाता है कि वे आज पारित आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से दस दिनों के भीतर आरोपी शुभम संगरा की आयु का जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से प्रभावित हुए बिना पता लगाएं।"

अदालत के आदेश की प्रमाणित प्रति पहले ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीपीओ) के माध्यम से पत्र संख्या द्वारा माननीय न्यायालय को भेज दी गई है। सीबी/एफआईआर/10-2018/154

दिनांक 16.03.2018। हालांकि, न्यायालय के आदेश की एक और फोटोकॉपी संदर्भ के लिए संलग्न की गई है, जिसे अनुलग्नक-डी के रूप में चिह्नित किया गया है।

5. तहसीलदार हीरानगर और ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण हीरानगर के उपरोक्त उत्तर और चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट के मद्देनजर, यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक शुभम सांगरा उर्फ चुबू को किशोर घोषित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि

इस जघन्य और घिनौने कृत्य में उसकी भूमिका और अब तक की जांच से सामने आए उसके आचरण और व्यवहार को देखते हुए, यह घोषित किया जाना चाहिए कि वह परिपक्व है, किशोर नहीं। इसके अलावा सीडी फाइल के अनुसार यह भी रिकॉर्ड पर रखा गया है कि शुभम सांगरा की गिरफ्तारी की तारीख 19.01.2018 है, न कि 12.01.2018 जैसा कि आवेदन में दर्शाया गया है।

उपरोक्त निवेदन के आलोक में, यह विनम्र निवेदन है कि उक्त आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाए और आवेदक शुभम संगरा उर्फ चुबू, पुत्र ओम प्रकाश, निवासी वार्ड संख्या 10, हीरानगर नेशनल पार्क, ग्राम रसाना, तहसील हीरानगर को वयस्क घोषित किया जाए, या वैकल्पिक रूप से किशोर घोषित न किया जाए, ताकि इस मामले की जांच योग्यता के आधार पर अंतिम रूप दी जा सके।

पुलिस अधीक्षक,

आई/जीएसआईटी अपराध शाखा, जम्मू-कश्मीर, जम्मू

19. उपर्युक्त अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से, मुख्य न्यायिक न्यायाधीश, कठुआ ने हीरा नगर नगर समिति के कार्यकारी अधिकारी और प्रतिवादी के पिता, ओम प्रकाश का बयान दर्ज किया।

20. अंततः, कठुआ के मुख्य न्यायिक न्यायाधीश ने 27.03.2018 को अंतिम आदेश पारित करते हुए प्रतिवादी को किशोर घोषित किया। कठुआ के मुख्य न्यायिक न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:

> *"उपरोक्त नियम 74 और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 8 के अनुसार किशोरता के निर्धारण संबंधी कानूनी स्थिति पर चर्चा करने के बाद, अब मामले के तथ्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाए।*

हीरानगर नगर समिति के कार्यकारी अधिकारी 23-03-2018 को याचिकाकर्ता की जन्मतिथि से संबंधित अभिलेखों के साथ उपस्थित हुए। उसी दिन उनकी परीक्षा ली गई। उनके अनुसार, उनके कार्यालय द्वारा रखे गए जन्म और मृत्यु रजिस्टर में याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 23-10-2002 दर्ज है; याचिकाकर्ता के माता-पिता ओम प्रकाश और श्रीमती तृप्ता हैं।" इसके अलावा, इस गवाह के अनुसार, याचिकाकर्ता की जन्मतिथि नगर समिति के अभिलेखों में 15-04-2004 को दर्ज की गई थी; उक्त प्रविष्टि तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी द्वारा की गई थी, जिनके हस्ताक्षर और मुहर संबंधित रजिस्टर के क्रमांक 80 पर अंकित हैं; यह प्रविष्टि प्रथम श्रेणी हीरानगर के कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश संख्या 22/ जेसी दिनांक 15-04-2004 के अनुसार दर्ज की गई थी; याचिकाकर्ता के पिता ने तत्कालीन कार्यकारी मजिस्ट्रेट (तहसीलदार) हीरानगर के समक्ष याचिकाकर्ता की जन्मतिथि दर्ज करने का निर्देश देने हेतु एक आवेदन दिया था; आदेश संख्या 22/ जेसी दिनांक 15-04-2004 के अनुसार, प्रथम श्रेणी हीरानगर के कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा ओम प्रकाश (याचिकाकर्ता के पिता) के तीन बच्चों की प्रविष्टि करने का निर्देश दिया गया था; याचिकाकर्ता की जन्मतिथि केवल प्रथम श्रेणी के कार्यकारी मजिस्ट्रेट के इस आदेश के अनुपालन में ही दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता के पिता के हस्ताक्षर संबंधित रजिस्टर के क्रमांक 80 पर मौजूद हैं; जन्म प्रमाण पत्र, जिसकी फोटोकॉपी इस न्यायालय की फाइल में है, उनके कार्यालय से जारी किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 23-10-2002 दर्ज है और यह प्रविष्टि मूल अभिलेख के अनुसार सही और सत्य है, इत्यादि।

जिरह के दौरान, गवाह ने बयान दिया कि मौजूदा कार्यकारी अधिकारी जन्म रजिस्टर में किसी भी आवेदन पर हस्ताक्षर अपनी उपस्थिति में सुनिश्चित करता है; नवजात शिशु के जन्म स्थान के संबंध में, प्रविष्टि आवेदक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर की जाती है और इस संबंध में कोई सत्यापन नहीं किया जाता है क्योंकि प्रविष्टि मजिस्ट्रेट के आदेश के आधार पर की जाती है;

यह भी कि आदेश संख्या 22/जेसी में याचिकाकर्ता के जन्म स्थान का उल्लेख नहीं है और वर्ष 2012 के बाद जन्म तिथि में प्रविष्टि से संबंधित आदेश न्यायालयों द्वारा जारी किए जाते हैं, न कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा, इत्यादि।

एक अन्य गवाह, ओम प्रकाश, जो याचिकाकर्ता सी के पिता हैं, की परीक्षा 24-03-2018 को ली गई।

इस गवाह के अनुसार, याचिकाकर्ता उनका सगा पुत्र है; याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 23-10-2002 है; याचिकाकर्ता की यह जन्मतिथि नगर समिति, हीरानगर के अभिलेख में भी दर्ज है और यह 15-04-2004 को दर्ज की गई थी; इससे पहले उन्होंने प्रथम श्रेणी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, हीरानगर के समक्ष याचिकाकर्ता की जन्मतिथि दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया था और साक्ष्य भी प्रस्तुत किए थे, जिसके परिणामस्वरूप तहसीलदार हीरानगर ने नगर समिति, हीरानगर के नाम से आदेश जारी किया, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 23-10-2002 दर्ज की गई; उनकी पत्नी का नाम तृप्ता देवी है। याचिकाकर्ता को मॉडर्न पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, हीरानगर में प्रथम कक्षा में प्रवेश दिया गया था; वहां भी उन्होंने याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 23-10-2002 बताई थी; याचिकाकर्ता को उक्त विद्यालय में 10 वर्ष पहले प्रवेश दिया गया था; हालांकि, विद्यालय के अभिलेखों में याचिकाकर्ता की जन्मतिथि गलत दर्ज की गई है। स्कूल में याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 23-10-2003 दर्ज है; उसे याचिकाकर्ता की जन्मतिथि की इस गलत प्रविष्टि के बारे में तब पता चला जब उसके (याचिकाकर्ता) खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद वह याचिकाकर्ता का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए स्कूल गया, इत्यादि।

क्रॉस-एग्जामिनेशन में, गवाह ने बयान दिया कि उसके तीन बच्चे हैं; जिनमें सबसे छोटा याचिकाकर्ता है। अज्ञानता के कारण उसने अपने बच्चों की जन्मतिथि दर्ज कराने के लिए 2004 में आवेदन किया, जबकि उसका सबसे बड़ा बच्चा 1996 में पैदा हुआ था; वह यह नहीं बता सकता कि शुभम संगरा को स्कूल में किस उम्र में दाखिला मिला था और वह शिक्षा विभाग में चौथे दर्जे का कर्मचारी है, इत्यादि।

यह ध्यान देने योग्य है कि हीरानगर नगर समिति के कार्यकारी अधिकारी के साक्ष्य से उस प्रक्रिया का स्पष्ट परिप्रेक्ष्य मिलता है जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता की जन्मतिथि वर्ष 2004 में हीरानगर नगर समिति के अभिलेख में दर्ज हुई थी। अभिलेख के अनुसार, यह स्थापित है कि याचिकाकर्ता की जन्मतिथि हीरानगर नगर समिति के जन्म रजिस्टर में पंजीकरण संख्या 80 के अंतर्गत 15-04-2004 को तत्कालीन प्रथम श्रेणी कार्यकारी मजिस्ट्रेट (तहसीलदार) हीरानगर द्वारा पारित आदेश संख्या 22/जेसी के अनुरूप दर्ज की गई थी। यह तथ्य कि उपरोक्त नगर समिति द्वारा 17-03-2018 को जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र मूल अभिलेख के अनुरूप है, नगर समिति के अभिलेखों और उसके कार्यकारी अधिकारी के साक्ष्य दोनों से स्पष्ट रूप से सिद्ध हो चुका है। हीरानगर नगर समिति द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में 17-03-2018 को जारी जन्म प्रमाण पत्र, जिसमें उनकी जन्म तिथि 2310-2002

दर्शाई गई है, उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में, इसे मनगढ़ंत, कृत्रिम या जाली नहीं कहा जा सकता है। साथ ही, जब याचिकाकर्ता के जन्म प्रमाण पत्र से प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की हेराफेरी या छल का आभास नहीं होता है, तो इसकी अत्यधिक जांच-पड़ताल पर विचार करना अनुचित है, यदि मैं ऐसा कहूँ, तो यह किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम की धारा 8 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम 74 के दायरे और सीमा पर ही एक त्रुटिपूर्ण टिप्पणी होगी। यह भी उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता के पिता द्वारा बताई गई कहानी हीरानगर नगर समिति के कार्यकारी अधिकारी और संबंधित आधिकारिक अभिलेखों द्वारा दिए गए विवरण से मेल खाती है।

इस मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे अनदेखा या नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वह यह है: याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 15-04-2004 को हीरानगर नगर समिति द्वारा आधिकारिक कामकाज के दौरान रखे गए जन्म रजिस्टर में दर्ज की गई थी। समिति ने यह प्रविष्टि स्वतःस्फूर्त रूप से नहीं बल्कि प्रथम श्रेणी कार्यकारी मजिस्ट्रेट हिरानगर द्वारा इस संबंध में जारी आदेश के अनुपालन में की थी। जिस घटना में याचिकाकर्ता की संलिप्तता का आरोप है, वह जनवरी 2018 की है। इसलिए यह कहना कि याचिकाकर्ता के पक्ष में जन्मतिथि इस प्रकार दर्ज कराई गई थी मानो उसे पता था कि तेरह वर्ष से अधिक समय बाद वह आपराधिक अभियोग में इसका लाभ उठाने की कोशिश करेगा, न केवल अतिशयोक्ति होगी बल्कि एक त्रुटिपूर्ण और निराधार धारणा भी होगी।

चूंकि संबंधित नगर समिति द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी जन्म प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया वैध पाया जाता है, इसलिए आयु निर्धारण के अन्य तरीकों का सहारा लेना स्वीकार्य नहीं है। यह मूलतः किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम 74 का दायित्व है।

उपरोक्त सभी चर्चाओं के आधार पर, और अधिनियम की धारा 8 तथा नियम 74 के प्रयोजन हेतु आवश्यक प्रमाण के मानक को ध्यान में रखते हुए, तथा प्रस्तुत प्रमाणों के आलोक में, यह माना जाता है कि हीरानगर नगर समिति द्वारा याचिकाकर्ता शुभम सांगरा के पक्ष में जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, जिसमें उनकी जन्म तिथि 23-10-2002 दर्शाई गई है, वैध, त्रुटिरहित और निष्पक्ष है, और अतः किशोर न्याय अधिनियम के प्रयोजन हेतु इसे मान्यता दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 23-10-2002 मानते हुए, यह माना जाता है कि इस आदेश के पारित होने की तिथि पर याचिकाकर्ता की आयु सोलह वर्ष से कम है।

माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 14-03-2018 के ओडब्ल्यूपी संख्या 259/2018 के निर्देश के अनुपालन में याचिकाकर्ता की आयु तदनुसार निर्धारित की गई है।

21. अपीलकर्ता राज्य, कठुआ के मुख्य न्यायिक न्यायाधीश द्वारा दिनांक 27.03.2018 को पारित उपरोक्त आदेश से असंतुष्ट और व्यथित होकर, उच्च न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर करके इसे चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए कठुआ के मुख्य न्यायिक न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा और प्रतिवादी को अपराध के घटित होने की तिथि पर किशोर माना। उच्च न्यायालय का विवादित आदेश इस प्रकार है:

> *26. यह स्वीकार किया जाता है कि नगर पालिका रिकॉर्ड और स्कूल रिकॉर्ड में प्रतिवादी की जन्मतिथि 23.10.2002 दर्ज है, जिसका अर्थ है कि एफआईआर दर्ज होने की तिथि पर उसकी आयु 18 वर्ष से कम थी। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने उपरोक्त रिकॉर्ड की प्रामाणिकता से इनकार नहीं किया है। जब नगर समिति के जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र के रूप में प्रतिवादी का स्पष्ट प्रमाण मौजूद है, तो प्रतिवादी की आयु के संबंध में चिकित्सा परीक्षण स्वतः ही अपना महत्व खो देता है।*
>
> *27. श्री पंत द्वारा उठाया गया अगला प्रश्न पुनरीक्षण याचिका की स्वीकार्यता के संबंध में है। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जबर सिंह बनाम दिनेश और अन्य 2010(3) एससीसी 757 में कहा है, पुनरीक्षण का दायरा बहुत सीमित है। निर्णय का प्रासंगिक अनुच्छेद नीचे दिया गया है:*
>
> > "29. अधिनियम की धारा 52 को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि न्यायालय के किसी भी ऐसे निर्णय के विरुद्ध कोई वैधानिक अपील उपलब्ध नहीं है जिसमें यह पाया गया हो कि अपराध करते समय कोई व्यक्ति किशोर नहीं था। अधिनियम की धारा 53, जिसका शीर्षक "पुनरीक्षण" है, यह प्रावधान करती है कि उच्च न्यायालय किसी भी समय, या तो स्वयं द्वारा या उस संबंध में प्राप्त आवेदन पर, किसी भी कार्यवाही का अभिलेख मंगवा सकता है जिसमें किसी सक्षम प्राधिकारी या सत्र न्यायालय ने किसी आदेश की वैधता या औचित्य की पुष्टि करने के उद्देश्य से कोई आदेश पारित किया हो, और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे। ऐसी पुनरीक्षण शक्तियों

का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय स्वयं को अपीलीय न्यायालय में परिवर्तित नहीं कर सकता और साक्ष्य या अभिलेख में मौजूद सामग्री के आधार पर निचली अदालत द्वारा दिए गए तथ्यों के निष्कर्षों को उलट नहीं सकता, सिवाय इसके कि उच्च न्यायालय निचली अदालत द्वारा पारित आदेश की वैधता या औचित्य से संतुष्ट न हो।"

28. याचिकाकर्ताओं ने स्वीकार किया है कि पुनरीक्षण का दायरा दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पुनरीक्षण के दायरे के समान है। याचिकाकर्ताओं द्वारा संदर्भित किशोर न्याय अधिनियम, 2013 की धारा 52 में भी यह उल्लेख है कि न्यायालय को किसी भी आदेश की वैधता और औचित्य की पुष्टि करनी होती है, अतः न्यायालय द्वारा तथ्यों के आधार पर दिए गए निष्कर्षों को तब तक रद्द नहीं किया जा सकता जब तक कि वे अनुचित न पाए जाएं। वर्तमान मामले में, जहां निचली अदालत द्वारा तथ्यात्मक निष्कर्ष दिया गया है, इसलिए आदेश में कोई अवैधता या अनुचितता नहीं है, अतः निचली अदालत के निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

29. इस मामले में, निचली अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर तथ्य संबंधी निष्कर्ष दिए हैं और 2014 के नियमों के नियम 74 के अनुरूप कार्य किया है, और तथ्य संबंधी निष्कर्षों में कोई विकृति नहीं है, अतः निचली अदालत ने कोई अवैधता या अनुचितता नहीं की है जिसके लिए इस पुनरीक्षण याचिका में हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। तदनुसार, यह

पुनरीक्षण याचिका संबंधित आपराधिक कार्यवाही सहित खारिज की जाती है।

यदि कोई अभिलेख उपलब्ध हो, तो उसे भेजा जाए। यदि कोई अंतरिम निर्देश हो, तो उसे निरस्त माना जाए।

(जम्मू ताशी राबस्तान)

11.10.2019 न्यायाधीश"

22. उपरोक्त के मद्देनजर अपीलकर्ता राज्य इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील लेकर उपस्थित है।

अपीलकर्ता राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँ:

23. अपीलकर्ता राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.एस. पटवालिया ने पुरजोर तर्क दिया कि मुख्य न्यायिक न्यायाधीश, कठुआ और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण कहा जा सकता है, जिससे न्याय व्यवस्था का मज़ाक उड़ता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दोनों आदेशों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि दोनों न्यायालयों ने किशोर की आयु निर्धारण से संबंधित वैधानिक नियमों को जानबूझकर अनदेखा किया है।

उन्होंने कहा कि ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है।रिकॉर्ड पर मौजूद स्पष्ट और ठोस दस्तावेजी साक्ष्य यह सुझाव देते हैं या इंगित करते हैं कि प्रतिवादी का जन्म 23.10.2002 को हुआ था। उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान हीरा नगर नगर समिति के कार्यकारी अधिकारी द्वारा दिनांक 15.04.2004 को पारित एक आदेश की ओर आकर्षित किया, जिसमें ओम प्रकाश संगरा के तीन बच्चों की जन्म तिथि और स्थान निर्दिष्ट किया गया है। दिनांक 15.04.2004 का यह आदेश प्रतिवादी के पिता ओम प्रकाश द्वारा जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1956 की धारा 19(3) और नियम 19(3) के तहत दायर आवेदन के अनुसरण में पारित किया गया था। आदेश इस प्रकार है:

"जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1956 की धारा 19(3) के तहत (अस्पष्ट) जम्मू एवं कश्मीर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के नियम 19(3) के साथ (अस्पष्ट) पुत्र राहुल संगरा, रिया संगरा, शुभम संगरा, जिला हीरानगर, तहसील हीरानगर के जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में आवेदन।

<u>आदेश</u>

आवेदक ने जन्म प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन किया है। आवेदक ओम प्रकाश संगरा ने बताया है कि उनका जन्म दिनांक 23-11-97, 21-2-98, 23-10-02 को ग्राम हीरानगर, तहसील हीरानगर में हुआ था और उन्होंने निवेदन किया है कि हीरानगर नगर निगम द्वारा उनकी जन्मतिथि दर्ज नहीं की गई है। आवेदक ने इस न्यायालय

में विधिवत शपथ पत्र सहित एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि संबंधित अधिकारियों की अनभिज्ञता के कारण उनकी जन्मतिथि दर्ज नहीं की जा सकी।

आवेदक ने अपने आवेदन में किए गए कथनों के समर्थन में स्वयं के अलावा तहसील हीरानगर निवासी राम कृष्ण के पुत्र (अस्पष्ट) को भी गवाह के रूप में प्रस्तुत किया है। आवेदक ने आवेदन की सामग्री का समर्थन किया है और हीरानगर, वार्ड संख्या 7, जिला कठुआ के आवेदक की ओर से उपस्थित गवाहों ने आवेदक के कथनों की पुष्टि की है।

मैंने आवेदन, हलफनामे और गवाहों के बयानों का अध्ययन किया है, उपरोक्त से यह स्थापित हो गया है कि आवेदक के पुत्र राहुल सांगरा की (अस्पष्ट) हत्या ग्राम तहसील हीरानगर में 23-11-97, 21-298 और 23-10-02 को हुई थी, इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री को ध्यान में रखते हुए आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त आवेदक का नाम _____ जन्म पंजीकरण और __ नियमों के नियम 19(3) के अनुसार उपर्युक्त __ के रजिस्टर में दर्ज किया जाए।

बच्चे का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	*नाम*	*पिता*	*दिनांक एवं जन्म स्थान*
1.	*राहुल सांगरा*	*ओम प्रकाश*	*23-11-97*
2.	*रिया सांगरा निवासी हीरानगर*		*21-02-98*
3.	*शुभम सांगरा*		*23-10-02*

नंबर: 22/जेसी *हस्ताक्षरित/-*

दिनांक 15-4-04 ..... हीरानगर

इस आदेश की प्रति एम.सी. को भेजी जाएगी। सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु हीरानगर।

हस्ताक्षर/-

कार्यकारी अधिकारी

नगर समिति

हीरानगर

24. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी की जन्म तिथि 23.10.2002 होने के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उपरोक्त आदेश पर भरोसा नहीं किया जा सकता था।

25. हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया कि ओमप्रकाश के पहले बच्चे, राहुल सांगरा का जन्म 23.11.1997 को दिखाया गया है, जबकि दूसरी संतान, यानी बेटी, रिया सांगरा का जन्म 23.01.1998 को दिखाया गया है, यानी सबसे बड़े बच्चे के जन्म के ठीक तीन महीने के भीतर प्रतिवादी डी की जन्म तिथि 23.10.2002 दिखाई गई है।

26. उपरोक्त के विपरीत, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान मॉडर्न पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल द्वारा जारी किए गए एक जन्म प्रमाण पत्र की ओर आकर्षित किया, जिसकी तिथि 13.10.2002 बताई गई है। 06.09.2017. इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

26. उपरोक्त के विपरीत, विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस न्यायालय का ध्यान मॉडर्न पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल द्वारा दिनांक 06.09.2017 को जारी किए गए एक जन्म प्रमाण पत्र की ओर आकर्षित किया। वह प्रमाण पत्र इस प्रकार है:

"मॉडर्न पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल

(10+2)

वार्ड संख्या 10-11 हीरानगर (कठुआ), जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और जम्मू-कश्मीर राज्य शिक्षा बोर्ड से संबद्ध

स्कूल

शिक्षा

क्रमांक *दिनांक 06/09/2017*

<u>प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओम प्रकाश/तृप्ता देवी के पुत्र शुभमसंगरा की जन्म तिथि (अंकों में) 23/10/2003 (शब्दों में) तेईस अक्टूबर, दो हजार तीन है, जैसा कि विद्यालय के अभिलेखों में दर्ज है।

उनका प्रवेश क्रमांक 1435 है। वे कक्षा 10वीं में पढ़ रहे थे।

पता

वार्ड संख्या 10, डाकघर हीरानगर, तहसील हीरानगर,

जिला कठुआ, पिन 184142

हस्ताक्षर/-

प्रधानाचार्य

मॉडर्न पब्लिक हायर सेकेंडरी

स्कूल

हीरानगर"

27. इस प्रकार, उपर्युक्त प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 23.10.2003 दर्शाई गई है। इसके बाद हमारा ध्यान मॉडर्न पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राथमिक विभाग के प्रवेश वापसी रजिस्टर के एक अंश की ओर आकर्षित हुआ, जो अनुलग्नक-पी-3 पेपर बुक के पृष्ठ 58 पर है, जिसमें प्रतिवादी का नाम क्रमांक 1757 पर है और जन्म तिथि 23.10.2003 दर्शाई गई है।

28. जन्म तिथि में उपरोक्त विरोधाभासों को उजागर करने के बाद, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने हमारा ध्यान जम्मू एवं कश्मीर किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) नियम, 2014 (संक्षेप में, 'नियम, 2014'), विशेष रूप से नियम 74 की ओर आकर्षित किया। नियम 74 आयु निर्धारण से संबंधित है। यद्यपि हमारे उद्देश्य के लिए नियम, 2014 के नियम 74

का उप-नियम (3) प्रासंगिक है, फिर भी हम संपूर्ण नियम 74 को यहाँ उद्धृत करना उचित समझते हैं, जो इस प्रकार है:

*"**74. आयु का निर्धारण.**–(1) जब भी कोई कथित अपराधी, जिसकी आयु 21 वर्ष से कम प्रतीत होती है, बोर्ड के अलावा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो वह न्यायालय प्रस्तुति की पहली तिथि को ही कथित अपराधी से उसकी आयु के बारे में पूछताछ करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वह किशोर नहीं है, इसके निष्कर्षों को नोट करें और जहां आवश्यक हो, मामले को तत्काल बोर्ड को स्थानांतरित करने का आदेश दें।*

(2) जब किसी किशोर या बच्चे को, या कानून से संघर्षरत किशोर को, बोर्ड या समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो वह प्रस्तुति की तिथि से तीस दिनों के भीतर उसकी आयु निर्धारित और घोषित करेगा।

(3) बोर्ड या समिति, जहाँ तक संभव हो, शारीरिक उपस्थिति या उपलब्ध दस्तावेजों (यदि कोई हो) के आधार पर किशोर होने या न होने का निर्णय करेगी। जहाँ बोर्ड या समिति द्वारा आयु निर्धारण हेतु कोई जाँच गठित की जाती है, ऐसी जाँच निम्नलिखित साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी:

(i) किसी निगम या नगर समिति या किसी अन्य अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र; या

(ii) मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र; या

(iii) उपखंड (i) और (ii) में उल्लिखित प्रमाण पत्रों के अभाव में या उनसे उत्पन्न किसी विरोधाभास की स्थिति में, आयु निर्धारण करने वाला प्राधिकारी मामले को विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड को भेज सकता है, जो अपने निष्कर्ष दर्ज करेगा और किशोर न्याय बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

(4) सभी सरकारी अस्पताल चिकित्सा आयु परीक्षा के लिए चिकित्सा बोर्ड का गठन करेंगे, जिसमें एक शरीर क्रिया विज्ञानी, एक दंत परीक्षक और एक रेडियोलॉजिस्ट या फोरेंसिक विशेषज्ञ शामिल होंगे, जिनमें से एक को अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।

(5) चिकित्सा बोर्ड के सभी सदस्य आयु संबंधी अपने-अपने निष्कर्ष देंगे, जिन्हें बोर्ड के अध्यक्ष को अंतिम राय देने के लिए एक वर्ष के भीतर भेजा जाएगा।

(6) विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड इस संबंध में अनुरोध प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर आयु संबंधी निष्कर्षों सहित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

29. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि नियम 74 के उप-नियम (3) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उप-नियम (3) के उपखंड (i) और (ii) में उल्लिखित प्रमाण पत्रों में किसी भी प्रकार का विरोधाभास होने पर, आयु निर्धारण करने वाला प्राधिकारी मामले को विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड को भेज सकता है, जो बदले में अपने निष्कर्ष दर्ज करेगा और उसे किशोर न्याय बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

30. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विभिन्न प्रमाण पत्रों के रूप में अभिलेखीय साक्ष्यों में स्पष्ट विरोधाभास है और ऐसी परिस्थितियों में मामले को विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड को भेजना आवश्यक था और अब आयु का निर्धारण अभिलेख में मौजूद चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर किया जाना है।

31. विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपराध करते समय प्रतिवादी की आयु 19 से 23 वर्ष के बीच हो सकती है।

32. अंत में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि यह मामला 8 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ किए गए एक अत्यंत जघन्य अपराध का है। उन्होंने कहा कि यदि नाबालिग होने का दावा या यह तथ्य कि आरोपी ने अपने जघन्य कृत्य के परिणामों को समझने की आयु प्राप्त नहीं की थी, अस्पष्टता या संदेह से मुक्त नहीं है, तो केवल संदिग्ध आयु प्रमाण पत्रों के आधार पर ऐसे दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और ऐसी परिस्थितियों में आरोपी की आयु निर्धारित करते समय चिकित्सा साक्ष्य को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। उपरोक्त संदर्भ में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **रामदेव चौहान उर्फ राज नाथ बनाम असम राज्य,** (2001) 5 एससीसी 714 में इस न्यायालय के निर्णय पर दृढ़तापूर्वक भरोसा जताया।

33. उपरोक्त परिस्थितियों में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पटवालिया ने प्रार्थना की कि उनकी अपील में योग्यता होने के कारण, इसे स्वीकार किया जाए और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को रद्द किया जाए और यह माना जाए कि अपराध के घटित होने की तिथि पर प्रतिवादी किशोर नहीं था।

<u>प्रतिवादी अभियुक्त की ओर से प्रस्तुतियाँ:</u>

34. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने इस अपील का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि निचली अदालतों द्वारा प्रतिवादी की आयु निर्धारित करने में कोई त्रुटि नहीं हुई है, विधि का कोई उल्लंघन तो दूर की बात है। उनके अनुसार, नियम 74 के उप-नियम (3) का इस मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है क्योंकि प्रतिवादी अभियुक्त की आयु प्रमाणित करने वाले प्रमाण पत्रों में कोई विरोधाभास नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रतिवादी अभियुक्त का जन्म 23.10.2002 को हुआ था, यह बात स्पष्ट है और यह वर्ष 2008 में हीरा नगर स्थित मॉडर्न पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रवेश के लिए विधिवत भरे गए प्रतिवादी के प्रवेश पत्र से भी स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि चाहे अपराध कितना भी जघन्य क्यों न हो, यदि कथित अपराध के घटित होने की तिथि पर अभियुक्त नाबालिग है, तो उस पर कानून के अनुसार नाबालिग के रूप में ही मुकदमा चलाया जाना चाहिए, न कि किसी अन्य अभियुक्त की तरह। उन्होंने यह तर्क दिया कि अपराध की जघन्यता या क्रूरता का किशोर न्याय अधिनियम के उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि चिकित्सा बोर्ड की राय पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि अंततः यह एक विशेषज्ञ की राय है और उम्र के संबंध में इसे निर्णायक नहीं माना जा सकता। विद्वान वकील ने ज़ोर देकर कहा कि न्यायालय इस प्रासंगिक तथ्य पर ध्यान दे कि इस मामले में ऐसा कोई प्रमाण पत्र/दस्तावेज़ नहीं है जो यह दर्शाता हो कि कथित अपराध की तिथि पर प्रतिवादी नाबालिग था या बालिग। उन्होंने तर्क दिया कि यदि जन्म तिथि दर्शाने वाला विद्यालय अभिलेख (प्रवेश पत्र) नियम 74 के उप-नियम (3) (ii) में उल्लिखित श्रेणी में नहीं आता है, तो नगर समिति द्वारा जारी आदेश संख्या 22/जे.सी./प्रमाण पत्र उपलब्ध होने के कारण, नियम 74(3)(ii) का सहारा लेना बिलकुल भी उचित नहीं है।

35. विद्वान वकील ने अपने उपरोक्त तर्कों के समर्थन में इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया:

(i) अश्वनी कुमार सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य,

(2012) 9 एससीसी 750

(ii) दरगा राम उर्फ गंगा बनाम राजस्थान राज्य,

(2015) 2 एससीसी 775

36. उपरोक्त परिस्थितियों में, प्रतिवादी अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना की कि इस अपील में कोई योग्यता न होने के कारण इसे खारिज कर दिया जाए।

विश्लेषण

37. पक्षों के अधिवक्ताओं की सुनवाई करने के बाद और अभिलेख में मौजूद सामग्री का अध्ययन करने के बाद, हमारे विचारणीय एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करने में कोई त्रुटि की है?

38. उपरोक्त अनुच्छेद 28 में संदर्भित नियम 74 के उप-नियम (3) से यह स्पष्ट होता है कि

उप-खंड (i) से (iii) में उल्लिखित प्रमाण पत्रों के अभाव में या उनसे उत्पन्न किसी भी विरोधाभास की स्थिति में, आयु निर्धारण का निर्णय करने वाला प्राधिकारी मामले को विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड को भेज सकता है, जो बदले में अपने निष्कर्ष दर्ज करेगा और किशोर न्याय बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। उपरोक्त हमारे द्वारा देखे गए अभिलेखीय साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी की जन्मतिथि से संबंधित अभिलेखीय प्रमाण पत्रों में विसंगतियां हैं। हम यह समझने में असमर्थ हैं कि निचली अदालतें ऐसी विसंगतियों या विरोधाभासों का संज्ञान क्यों नहीं ले पाईं। हम प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत इस तर्क से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हैं कि यदि अभिलेखीय साक्ष्यों में विरोधाभास या विसंगतियां हैं, तब भी अभिलेख में ऐसी कोई तिथि नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि कथित अपराध की तिथि पर प्रतिवादी बालिग था। यह एक अत्यंत तर्कहीन दलील है। मूल मुद्दे को देखने का यह सही तरीका नहीं है। मूल मुद्दे को देखने का सही तरीका यह है कि अभियुक्त की सही जन्मतिथि के संबंध में कोई ठोस या विश्वसनीय साक्ष्य है या नहीं, इसकी गहन जांच की जाए और इसकी पुष्टि करने के बाद उचित निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। यदि इस संबंध में कोई संदेह है, तो मामले को विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड को भेजने में कोई उचित कारण नहीं है,

जो बदले में अपने निष्कर्ष दर्ज करेगा और किशोर न्याय बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। नियम 74 के उप-नियम (3) के मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, "संभव होना" शब्द को "करेगा" पढ़ा जाना चाहिए।

39. व्याख्या का यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी विधान में 'मे' शब्द का प्रयोग अपने आप में निर्देशात्मक अर्थ नहीं देता है। यदि किसी विशेष मामले में, निष्पक्षता और न्याय के हित में न्यायालय को प्रतीत होता है कि विधायिका का आशय एक वैधानिक कर्तव्य को व्यक्त करना है, तो 'मे' शब्द का प्रयोग न्यायालय को इसे अनिवार्य रूप देने से नहीं रोकेगा। इस न्यायालय ने **बाचाहन देवी बनाम नगर निगम, गोरखपुर** (2008) 12 एससीसी 372 में निम्नलिखित निर्णय दिया:

> *"18. यह सर्वविदित है कि किसी विधिक प्रावधान में "हो सकता है" शब्द का प्रयोग मात्र यह सिद्ध नहीं करता कि वह प्रावधान निर्देशात्मक प्रकृति का है। कुछ मामलों में, विधायिका "हो सकता है" शब्द का प्रयोग केवल औपचारिक शिष्टाचार के रूप में कर सकती है और फिर भी उसका अर्थ बाध्यकारी हो सकता है। अतः, "हो सकता है" शब्द के कानूनी अर्थ की व्याख्या करने के लिए न्यायालय को विभिन्न कारकों पर विचार करना होगा, अर्थात् अधिनियम का उद्देश्य और योजना, वह संदर्भ और पृष्ठभूमि जिसमें इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, इस शब्द के प्रयोग से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य और लाभ, इत्यादि।" यह सर्वविदित है कि जहाँ "हो सकता है" शब्द किसी दायित्व के साथ विवेकाधिकार को दर्शाता है, या जहाँ यह किसी उपयोगिता अधिनियम में नागरिकों के एक सामान्य वर्ग को सकारात्मक लाभ प्रदान करता है, या जहाँ न्यायालय किसी उपाय को आगे बढ़ाता है और गड़बड़ी को रोकता है, या जहाँ इन शब्दों को निर्देशात्मक अर्थ देना अधिनियम के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देगा, वहाँ "हो सकता है" शब्द की व्याख्या अनिवार्य बल के साथ की जानी चाहिए। सामान्यतः, "हो सकता है" शब्द विवेकाधिकार प्रदान करने के लिए अनुज्ञात्मक और क्रियाशील होता है, और विशेष रूप से तब, जब इसका प्रयोग "हो सकता है" शब्द के साथ किया जाता है, जो आमतौर पर अनिवार्य होता है क्योंकि यह एक कर्तव्य थोपता है। हालाँकि, ऐसे मामले भी मौजूद हैं जहाँ "हो सकता है" और "अवश्य" शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। यह पता लगाने के लिए कि इन शब्दों का प्रयोग निर्देशात्मक या अनिवार्य*

अर्थ में किया जा रहा है, प्रासंगिक परिस्थितियों के साथ-साथ विधायिका के इरादे पर भी विचार किया जाना चाहिए।

40. इसी प्रकार, इस न्यायालय ने धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2007) 8 एससीसी 338 में कहा:

"36. ....हमारे मत में, मात्र "हो सकता है" या "होगा" शब्दों का प्रयोग निर्णायक नहीं है। किसी क़ानून का कोई विशेष प्रावधान निर्देशात्मक है या अनिवार्य, यह प्रश्न किसी सार्वभौमिक नियम को निर्धारित करके हल नहीं किया जा सकता। ऐसे विवाद का निर्णय विधायिका के आशय का पता लगाकर किया जाना चाहिए, न कि प्रावधान की भाषा को देखकर। और विधायी आशय का पता लगाने के लिए, न्यायालय को अधिनियम की योजना, प्रावधान के अंतर्निहित उद्देश्य, प्रावधान को एक या दूसरे तरीके से पढ़ने पर होने वाले संभावित परिणाम या असुविधा, और इस मुद्दे से संबंधित कई अन्य विचारों की जांच करनी चाहिए।"

41. हम अधिनियम, 2013 की धारा 8 का भी उल्लेख कर सकते हैं। धारा 8 में उस प्रक्रिया का प्रावधान है जिसका पालन तब किया जाना चाहिए जब किसी न्यायालय के समक्ष किशोरता का दावा उठाया जाता है। धारा 8 इस प्रकार है:

"***8. किसी न्यायालय के समक्ष किशोर होने का दावा उठाए जाने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया.***–*(1) जब भी किसी न्यायालय के समक्ष किशोर होने का दावा उठाया जाता है या न्यायालय की राय है कि यदि कोई अभियुक्त व्यक्ति अपराध के घटित होने की तिथि पर किशोर था, तो न्यायालय जांच करेगा, ऐसे साक्ष्य लेगा जो आवश्यक हों (परन्तु शपथपत्र नहीं) ताकि ऐसे व्यक्ति की आयु निर्धारित की जा सके, और यह निष्कर्ष दर्ज करेगा कि व्यक्ति किशोर है या नहीं, उसकी आयु यथासंभव निकट बताते हुए:*

बशर्ते कि किशोर होने का दावा किसी भी न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है और इसे किसी भी स्तर पर, यहां तक कि मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी, मान्यता दी जाएगी, और ऐसे दावे का निर्धारण अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, भले ही अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि को या उससे पहले किशोर न रहा हो।

42. उपर्युक्त धारा 8 के स्पष्ट अर्थ से यह स्पष्ट होता है कि जब भी किसी न्यायालय के समक्ष किशोर होने का दावा उठाया जाता है या न्यायालय की राय है कि अपराध के घटित होने की तिथि पर अभियुक्त व्यक्ति किशोर था, तो न्यायालय के लिए जांच करना अनिवार्य है और ऐसी जांच के दौरान, न्यायालय ऐसे साक्ष्य यद्यपि शपथपत्र नहीं हो ले सकता है जो आवश्यक हो, , ताकि उस व्यक्ति की आयु निर्धारित की जा सके। जांच के अंत में, यदि न्यायालय धारा 8 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपराध के घटित होने की तिथि पर किसी व्यक्ति को किशोर पाता है, तो ऐसी परिस्थिति में, न्यायालय कानूनन किशोर को उचित आदेश और सजा पारित करने के लिए किशोर न्याय बोर्ड को भेजने के लिए बाध्य है।

43. हम अधिनियम, 2013 की धारा 48 पर भी विचार कर सकते हैं। धारा 48 आयु के अनुमान और निर्धारण से संबंधित है। धारा 48 इस प्रकार है:

*"48. **आयु का अनुमान एवं निर्धारण.**–(1) यदि किसी सक्षम प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि अधिनियम के किसी प्रावधान के अंतर्गत उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति (साक्ष्य देने के उद्देश्य के अतिरिक्त) किशोर या बच्चा है, तो सक्षम प्राधिकारी उस व्यक्ति की आयु के संबंध में विधिवत जांच करेगा और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक साक्ष्य लेगा (परन्तु शपथपत्र नहीं) और यह निष्कर्ष दर्ज करेगा कि वह व्यक्ति किशोर या बच्चा है या नहीं।"*

उपधारा (1) के तहत अपराध किए जाने की स्थिति में, यह किशोर को उचित आदेश पारित करने के लिए बोर्ड को भेजेगा और यदि किसी न्यायालय द्वारा कोई सजा दी गई है, तो वह अप्रभावी मानी जाएगी।

(2) किसी सक्षम प्राधिकारी का कोई भी आदेश केवल इस आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा कि जिस व्यक्ति के संबंध में आदेश दिया गया है वह किशोर या बच्चा नहीं है, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस व्यक्ति की आयु के रूप में दर्ज की गई आयु, जिसे उसके समक्ष लाया गया है, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उस व्यक्ति की वास्तविक आयु मानी जाएगी।

44. ऊपर उल्लिखित धारा 48 एक सक्षम प्राधिकारी के बारे में बात करती है, जबकि ऊपर उल्लिखित अधिनियम 2013 की धारा 8 न्यायालय के संबंध में है। हालांकि, ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोनों धाराओं, अर्थात् धारा 8 और धारा 48, में 'करेंगे ' शब्द का प्रयोग किया गया है।

45. इस मामले का एक और पहलू है। उच्च न्यायालय ने ही दिनांक 21.02.2018 का आदेश पारित करना उचित समझा, जिसका उल्लेख हमने उपरोक्त अनुच्छेद 9 में किया है, जिसमें विशेष जांच दल (एसआईटी) को प्रतिवादी की आयु का पता लगाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया था।

> उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए ऐसे निर्देशों के अनुसार ही विभिन्न विषयों के पांच चिकित्सा विशेषज्ञों से मिलकर एक विशेष चिकित्सा बोर्ड का गठन किया गया था और हम प्रतिवादी की अनुमानित आयु के संबंध में इसी पांच चिकित्सा विशेषज्ञों वाले चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं। जब हम इस निष्कर्ष पर पहुँच गए हैं कि कथित अपराध की तिथि पर अभियुक्त की जन्मतिथि या आयु के संबंध में रिकॉर्ड पर कोई ठोस और विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद नहीं है, तो हमारे पास विशेष चिकित्सा बोर्ड द्वारा तैयार की गई चिकित्सा रिपोर्ट को न देखने या अनदेखा करने का कोई अच्छा कारण नहीं है, जो रिकॉर्ड पर मौजूद है।
>
> ऐसी परिस्थितियों में, नियम 74 के उप-नियम (3)(iii) की प्रयोज्यता के संबंध में प्रतिवादी की ओर से दिया गया तर्क महत्वहीन हो जाता है। दूसरे शब्दों में, यह तर्क कि विशेष चिकित्सा बोर्ड का गठन नहीं किया जाना चाहिए था, महत्वहीन हो जाता है क्योंकि विशेष बोर्ड का गठन उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के तहत किया गया था।

46. आइए देखें कि इस न्यायालय ने **दरगा राम @ गंगा** (उपरोक्त) मामले में क्या कहा है, जिस पर प्रतिवादी अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने दृढ़तापूर्वक भरोसा किया है। दरगा राम @ गंगा (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:

"*16. विधिवत गठित बोर्ड द्वारा दी गई चिकित्सा राय, जिसमें शरीर रचना विज्ञान, रेडियोडायग्नोसिस और फोरेंसिक मेडिसिन के प्रोफेसर शामिल हैं, ने परीक्षा की तिथि पर उनकी आयु लगभग 33 वर्ष निर्धारित की है। बोर्ड चिकित्सा परीक्षण के आधार पर अपीलकर्ता की सटीक आयु निर्धारित करने में असमर्थ रहा है, चाहे उस क्षेत्र में कितनी भी प्रगति क्यों न हुई हो। ऐसे में, नियम 12(3)(ख) के अनुसार, यदि न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक समझे, तो अपीलकर्ता को एक वर्ष के अंतर से अपनी आयु कम निर्धारित करने का लाभ भी मिल सकता है। हालांकि, इस तरह की किसी वैधानिक छूट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यदि चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्धारित अनुमानित आयु को भी*

अपीलकर्ता की सही/ वास्तविक आयु मान लिया जाए, तो घटना की तिथि पर वह लगभग 17 वर्ष और 2 महीने का था और इस प्रकार उपर्युक्त अधिनियम में प्रयुक्त शब्द के अर्थ में एक किशोर था। यह सब कहने के बाद, हम यह कहने से खुद को नहीं रोक सकते कि हम इससे पूरी तरह सहमत नहीं हैं। चिकित्सा बोर्ड ने चिकित्सा परीक्षण की तिथि पर अपीलकर्ता की आयु 30 से 36 वर्ष के बीच अनुमानित की है।

17. आयु निर्धारण का सामान्य नियम यह है कि निर्धारित आयु में दो वर्ष की छूट हो सकती है, लेकिन बोर्ड ने इस मामले में छह वर्षों की अवधि में औसत निकालकर अपीलकर्ता की आयु 33 वर्ष निर्धारित की है। हमें यकीन नहीं है कि अपीलकर्ता की आयु का अनुमान लगाने का यह सही तरीका है। आयु के अनुमान के बारे में हमें जो बात आश्वस्त करती है, वह यह है कि यह एक चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है जिसमें शरीर रचना विज्ञान, रेडियोडायग्नोसिस और फोरेंसिक मेडिसिन के प्रोफेसर शामिल हैं, जिनकी राय का सम्मान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यदि अपीलकर्ता की आयु ऊपरी सीमा यानी 36 वर्ष के आधार पर भी निर्धारित की जाती, तो भी इसमें दो वर्ष की छूट हो सकती थी, जिसका अर्थ है कि परीक्षण की तिथि पर उसकी आयु 34 वर्ष भी हो सकती थी। अभियुक्त की आयु को परीक्षा की तारीख पर 34 वर्ष मानते हुए, घटना की तारीख पर उसकी आयु 18 वर्ष, 2 महीने और 7 दिन होती, लेकिन यह केवल एक अनुमान होगा और अभियुक्त को नियम 12(3)(ब) के तहत एक वर्ष की अतिरिक्त छूट का लाभ मिल सकता है, जिससे उसकी आयु 17 वर्ष और 2 महीने हो जाएगी, इसलिए उसे जुवेनाइल माना जाएगा।

47. दूसरी ओर, अपीलकर्ता राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि **दरगा राम @ गंगा** (उपरोक्त) मामले पर इस न्यायालय द्वारा **मुकर्रब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** (2017) 2 एससीसी 210 के मामले में विचार किया गया था, और **मुकर्रब** (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

"22. **दरगा राम मामले** (उपरोक्त) के उपरोक्त निर्णय को पढ़ने से पता चलता है कि न्यायालयों को इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि मूल और वैध दस्तावेजी प्रमाण के अभाव में संबंधित व्यक्तियों की आयु का निर्धारण निश्चित रूप से नहीं किया जा सकता है और हमेशा यह संभावना बनी रहती है कि संबंधित व्यक्ति की आयु में दो वर्ष कम या ज्यादा का अंतर हो सकता है। चिकित्सा राय की उपस्थिति में भी, न्यायालय ने आरोपी के किशोर होने की ओर झुकाव दिखाया। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दरगा राम मामले (उपरोक्त) में ऐसा दृष्टिकोण उस विशेष मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में अपनाया

गया था और उक्त दृष्टिकोण को सामान्य बनाने का कोई भी प्रयास उचित नहीं ठहराया जा सकता है।"

48. इस प्रकार, **मुकर्रब** (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दरगा राम @ गंगा (उपरोक्त) का निर्णय उस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया गया था और उक्त दृष्टिकोण को सामान्यीकृत करने का कोई भी प्रयास उचित नहीं ठहराया जा सकता।

49. आगे बढ़ने से पहले, हम यह स्पष्ट कर दें कि **दरगा राम @ गंगा** (उपरोक्त) का मामला किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 (संक्षेप में, 'अधिनियम, 2000') के अंतर्गत था। हम अधिनियम, 2000 के तहत किशोरता का दावा उठाए जाने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में एक उचित विचार दे सकते हैं।

50. अधिनियम, 2000 की धारा 7ए इस प्रकार है:

"7ए. किसी न्यायालय के समक्ष किशोरता का दावा उठाए जाने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया-

(1) जब भी किसी न्यायालय के समक्ष किशोरता का दावा उठाया जाता है या यदि न्यायालय की राय है कि अपराध किए जाने की तिथि पर कोई आरोपी व्यक्ति किशोर था, तो न्यायालय उसकी आयु यथासंभव बताते हुए जांच करेगा और ऐसे साक्ष्य लेगा जो आवश्यक हो (परन्तु शपथ पत्र नहीं) ताकि ऐसे व्यक्ति की आयु निर्धारित की जा सके, और यह निष्कर्ष दर्ज करेगा कि क्या व्यक्ति एफ किशोर या बच्चा है या नहीं,:

बशर्ते कि किशोरता का दावा किसी भी न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है और इसे किसी भी स्तर पर, यहां तक कि मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी, मान्यता दी जाएगी, और ऐसे दावे का निर्धारण इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, भले ही किशोर इस अधिनियम के लागू होने की तिथि को या उससे पहले यह स्थिति समाप्त हो गई है।

(2) यदि न्यायालय उपधारा (1) के अंतर्गत अपराध किए जाने की तिथि पर किसी व्यक्ति को किशोर पाता है, तो वह किशोर को उचित आदेश पारित करने हेतु बोर्ड को भेजेगा और न्यायालय द्वारा पारित कोई भी सजा अप्रभावी मानी जाएगी।

51. धारा 7ए को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब भी किशोर होने का दावा उठाया जाता है, तो एक जांच की जानी चाहिए और ऐसी जांच साक्ष्य प्राप्त करके की जाएगी जो

आवश्यक होगा, ताकि ऐसे व्यक्ति की आयु निर्धारित की जा सके, यह एक शपथ पत्र नहीं होगा ।

52. आयु निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया 2007 के नियमों के नियम 12(3)(ख) के अंतर्गत दी गई है, जो इस प्रकार है:

"***12. आयु निर्धारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया.***– *(3) कानून से संघर्षरत किसी बच्चे या किशोर के मामले में, आयु निर्धारण की जांच न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति द्वारा निम्नलिखित साक्ष्य प्राप्त करके की जाएगी:*

(क)(i) मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और इनके अनुपलब्ध होने पर;

(ii) उस विद्यालय (प्ले स्कूल को छोड़कर) से जन्म प्रमाण पत्र जिसमें बच्चे ने पहली बार शिक्षा प्राप्त की थी; और इनके अनुपलब्ध होने पर;

(iii) किसी निगम या नगर पालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र;

(ख) और केवल उपरोक्त खंड (क) के (i), (ii) या (iii) में से किसी के अनुपलब्ध होने पर, विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा राय ली जाएगी, जो किशोर या बच्चे की आयु घोषित करेगा। यदि आयु का सटीक आकलन संभव न हो, तो न्यायालय, बोर्ड या समिति, अपने द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर, यदि आवश्यक समझे तो, बच्चे या किशोर को उसकी आयु में एक वर्ष की छूट देकर लाभ प्रदान कर सकती है और ऐसे मामले में आदेश पारित करते समय, उपलब्ध साक्ष्यों या चिकित्सकीय राय पर विचार करने के बाद, उसकी आयु के संबंध में निष्कर्ष दर्ज करेगा और खंड (क)(i), (ii), (iii) में निर्दिष्ट साक्ष्यों में से कोई एक या इनके अभाव में खंड (ख) ऐसे बच्चे या कानून से संघर्षरत किशोर की आयु का निर्णायक प्रमाण होगा।

53. उपर्युक्त नियम के उपखंड (3) में स्पष्ट रूप से यह अनिवार्य किया गया है कि किसी अभियुक्त की किशोरता के संबंध में जांच करते समय, किशोर न्याय बोर्ड मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र प्राप्त करके साक्ष्य मांगेगा, और यदि ये प्रमाण पत्र उपलब्ध न हों तो प्रथम विद्यालय से प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र, और यदि ये भी उपलब्ध न हों तो निगम, नगर पालिका या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र मांगेगा । उपखंड (ख) में यह स्पष्ट किया

गया है कि उपर्युक्त तीनों दस्तावेजों के अनुपलब्ध होने पर ही विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा संबंधी जानकारी मांगी जाएगी, जो किशोर या बच्चे की आयु घोषित करेगा। इस प्रकार, उपर्युक्त दस्तावेजों के अनुपलब्ध होने पर ही किशोर न्याय बोर्ड चिकित्सा संबंधी जानकारी/ अस्थि निर्माण परीक्षण का अनुरोध कर सकता है।

54. **मुकर्रब** (उपरोक्त) का मामला भी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत था।

55. अब हम **अश्वनी कुमार सक्सेना** (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर विचार करेंगे, जिसमें इस न्यायालय ने पैरा 34 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:

*"**34**. ... ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्रों, प्रथम विद्यालय से प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र और यहाँ तक कि किसी निगम, नगर पालिका या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज जानकारी सही न हो। लेकिन न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड या किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत कार्य करने वाली किसी समिति से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह इस प्रकार की विस्तृत जाँच करे और सामान्य कामकाज के दौरान रखे गए उन दस्तावेजों की सत्यता की जाँच करने के लिए उन प्रमाण पत्रों के पीछे जाए। केवल उन मामलों में जहाँ वे दस्तावेज या प्रमाण पत्र जाली या हेरफेर किए हुए पाए जाते हैं, न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड या समिति को आयु निर्धारण के लिए चिकित्सा रिपोर्ट की आवश्यकता होती है।"*

56. ऊपर संदर्भित **अश्वनी कुमार सक्सेना** (उपरोक्त) भी अधिनियम, 2000 से संबंधित है।

57. उपरोक्त बातों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने **अश्वनी कुमार सक्सेना** (उपरोक्त) मामले में "जांच, छानबीन और परीक्षण" शब्दों के बीच मूलभूत अंतरों की जांच की, जैसा कि हमें दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में "सीआरपीसी") में मिलता है। इसके बाद न्यायालय ने यह माना कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत जांच करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया वही है जो उसी अधिनियम में निर्धारित है, अर्थात् 2007 के नियमों का नियम 12, और यह माना कि किशोर न्याय अधिनियम और नियमों के तहत परिकल्पित आयु निर्धारण जांच का सेवा में प्रवेश, सेवानिवृत्ति और पदोन्नति जैसे अन्य कानूनों के तहत की जाने वाली जांच से कोई संबंध नहीं है। न्यायालय ने कहा कि जहां स्कूल प्रमाणपत्रों में दर्ज जानकारी उपलब्ध है, वहां न्यायालय या किशोर न्याय बोर्ड से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह विस्तृत जांच करे और उन प्रमाणपत्रों से परे जाकर उनकी सत्यता की जांच करे, क्योंकि ये दस्तावेज सामान्य कामकाज के दौरान रखे गए हैं। न्यायालय ने माना कि स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र सहित

दस्तावेजों की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी और इस संबंध में कोई कठोर नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी माना कि प्रमाण पत्रों को इस आधार पर संदिग्ध नहीं माना जाना चाहिए कि माता-पिता आमतौर पर प्रवेश रजिस्टर में गलत जन्मतिथि दर्ज करवा देते हैं। प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने **अश्वनी कुमार सक्सेना** (उपरोक्त) के फैसले का हवाला देते हुए यह तर्क दिया कि न्यायालय को व्यापक जांच नहीं करनी चाहिए और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्यों से आगे नहीं जाना चाहिए।

58. इस न्यायालय ने ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2022) 8 एससीसी 602 में, अपने निम्नलिखित पूर्ववर्ती निर्णयों पर उचित विचार करने के बाद, निम्नलिखित निर्णय दिए:

(i) **पराग भाटी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,**

(2016) 12 एससीसी 744,

(ii) **संजीव कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**,

(2019) 12 एससीसी 370,

(iii) **अबुजर हुसैन उर्फ गुलाम हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य,**

(2012) 10 एससीसी 489,

(iv) **अश्वनी कुमार सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य,**

(2012) 9 एससीसी 750,

(v) **बबलू पासी बनाम झारखंड राज्य,**

(2008) 13 एससीसी 133,

(vi) **अर्निंत दास बनाम बिहार राज्य,**

(2000) 5 एससीसी 488,

(vii) **जितेंद्र राम उर्फ जीतू बनाम झारखंड राज्य,**

(2006) 9 एससीसी 428

ने दो अधिनियमों, अर्थात् अधिनियम, 2000 और किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संक्षेप में, 'अधिनियम, 2015') के तहत प्रक्रिया में अंतर की ओर इशारा किया, जिसमें किशोर की आयु निर्धारण की जांच और साक्ष्य मांगने की शक्ति, उस शक्ति का प्रयोग कैसे और कब किया जाए और कब अस्थिभवन परीक्षण किया जाए, शामिल है।

इस न्यायालय ने माना कि प्रत्येक मामले को उसके विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में निपटाया जा सकता है, जबकि कुछ सिद्धांतों को मार्गदर्शक कारक के रूप में ध्यान में रखा जाए, जैसा कि इस न्यायालय के निर्णय के अंतिम पैराग्राफ में वर्णित है। हम अंतिम पैराग्राफ को थोड़ी देर बाद पुनः प्रस्तुत करेंगे।

59. **ऋषिपाल सिंह सोलंकी** (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने न्यायधीश नियम, 2007 के नियम 12 और अधिनियम, 2015 की धारा 94 की उपधारा (2) के बीच मूल प्रावधानों के रूप में समानता की ओर इशारा किया। इस न्यायालय ने **अश्वनी कुमार सक्सेना (उपरोक्त) और अबुजर हुसैन @ गुलाम हुसैन** (उपरोक्त) के अपने निर्णयों का हवाला देते हुए इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि केवल उन्हीं मामलों में जहां प्रमाण पत्र जाली और हेरफेर किए गए पाए जाते हैं,

किशोर न्याय बोर्ड को चिकित्सा रिपोर्ट पर विचार करने की आवश्यकता होती है और इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि स्कूल प्रमाण पत्रों पर भरोसा करने का मापदंड थोड़ा अलग हो सकता है जहां स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या मतदाता सूची आदि दोषसिद्धि के बाद प्राप्त की जाती है।

60. इस प्रकार, इस न्यायालय ने किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दस्तावेजों/ प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखा, इससे पहले कि उन दस्तावेजों पर भरोसा किया जा सके। दूसरे शब्दों में, भले ही दस्तावेज प्रथम दृष्टया सही पाए जाएं, फिर भी ऐसे तथ्य और परिस्थितियां हो सकती हैं जो न्यायालय को दावे की सत्यता की जांच करने के लिए सचेत करें। इसी संदर्भ में, इस न्यायालय ने **अबूजर हुसैन उर्फ गुलाम हुसैन** (उपरोक्त) के फैसले में दिए गए एक मत का उल्लेख किया कि जब कोई दावेदार या उसके माता-पिता या भाई-बहन पहली बार अपील या पुनरीक्षण में किशोर होने के दावे के समर्थन में केवल हलफनामों पर निर्भर करते हैं, तो यह आयु निर्धारण के लिए जांच को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जब तक कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद न हों जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

61. **संजीव कुमार गुप्ता** (उपरोक्त) मामले में, अधिनियम, 2000 की धारा 7(ए) के तहत आयु निर्धारण हेतु मैट्रिक प्रमाण पत्र की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता पर विचार किया गया था। उक्त मामले में, किशोर न्याय बोर्ड ने किशोर होने के दावे को खारिज कर दिया था और इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को अस्वीकार करते हुए किशोर न्याय बोर्ड के उस निर्णय को बहाल कर दिया था। इसमें यह पाया गया कि सीबीएसई द्वारा रखे गए अभिलेख पूरी तरह से उस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय द्वारा भेजे गए छात्रों की अंतिम सूची पर आधारित थे, जहाँ किशोर ने कक्षा 5 से 10 तक शिक्षा प्राप्त की थी, न कि किसी अन्य अंतर्निहित दस्तावेज़ पर। दूसरी ओर, जन्म तिथि का स्पष्ट और निर्विवाद प्रमाण था, जो दूसरे विद्यालय के अभिलेखों में दर्ज था, जहाँ द्वितीय प्रतिवादी ने कक्षा 4 तक शिक्षा प्राप्त की थी, और जिसका समर्थन आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करते समय आरोपी द्वारा स्वेच्छा से किए गए खुलासे से भी होता है। यह देखा गया कि मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को प्रामाणिक या विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। उक्त मामले में, यह माना गया कि द्वितीय प्रतिवादी की जन्म तिथि 17.12.1995 थी और वह नाबालिग होने का दावा करने का हकदार नहीं था क्योंकि कथित घटना की तिथि 18.08.2015 थी।

62. इस न्यायालय ने **संजीव कुमार गुप्ता** (उपरोक्त) मामले में **अश्वनी कुमार सक्सेना** (उपरोक्त) और **अबुजर हुसैन उर्फ गुलाम हुसैन** (उपरोक्त) के निर्णयों पर विचार किया और यह पाया कि स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र सहित दस्तावेजों की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी और इस संबंध में कोई कठोर नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय ने **अबुजर हुसैन उर्फ गुलाम हुसैन** (उपरोक्त) मामले में अपनी टिप्पणी को दोहराया है, जो नीचे दी गई है:

"48. *...जांच का निर्देश देना और अभियुक्त को किशोर घोषित करना एक ही बात नहीं है। दोनों के लिए आवश्यक प्रमाण का मानक अलग-अलग है। पहले मामले में, न्यायालय केवल प्रथम दृष्टया निष्कर्ष दर्ज करता है। दूसरे मामले में, न्यायालय साक्ष्य के आधार पर घोषणा करता है, जिसकी वह गहन जांच करता है और उसे तभी स्वीकार करता है जब वह स्वीकार करने योग्य हो। ..."*

63. **अबूजर हुसैन** (उपरोक्त) भी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत है।

64. **ऋषिपाल सिंह सोलंकी** (उपरोक्त) में, अपने सभी पूर्व निर्णयों पर उचित विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:

"33. उपरोक्त निर्णयों की श्रृंखला पर संचयी विचार करने से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलता है:

33.1. किशोर होने का दावा किसी भी आपराधिक कार्यवाही के किसी भी चरण में उठाया जा सकता है, यहां तक कि मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी।

किशोर होने का दावा उठाने में देरी ऐसे दावे को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती।

इसे पहली बार इस न्यायालय के समक्ष भी उठाया जा सकता है।

33.2. एक किशोर होने का दावा करने वाला आवेदन न्यायालय या न्याय न्याय बोर्ड के समक्ष किया जा सकता है।

33.2.1. जब किशोर होने का मुद्दा न्यायालय के समक्ष उठता है, तो

यह न्याय न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 9 की उपधारा (2) और (3) के अंतर्गत होगा, लेकिन जब किसी व्यक्ति को समिति या न्याय न्याय बोर्ड के समक्ष लाया जाता है, तो न्याय न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 लागू होती है।

33.2.2. यदि न्यायालय के समक्ष किशोर होने का दावा करते हुए आवेदन दायर किया जाता है, तो न्याय न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 की उपधारा (2) का प्रावधान लागू किया जाना चाहिए या धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पढ़ा जाना चाहिए ताकि व्यक्ति की आयु को यथासंभव सटीक रूप से बताने वाले निष्कर्ष को दर्ज करने के उद्देश्य से साक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

33.2.3. जब न्याय न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 के तहत न्याय न्याय बोर्ड के समक्ष किशोर होने का दावा करते हुए आवेदन किया जाता है, जबकि कथित अपराध के संबंध में मामला न्यायालय में लंबित है, तो न्याय न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 के तहत निर्धारित प्रक्रिया लागू होगी। उक्त प्रावधान के तहत, यदि न्याय न्याय बोर्ड को इस संबंध में संदेह के लिए उचित आधार हैं कि उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बच्चा है या नहीं, तो बोर्ड साक्ष्य प्राप्त करके आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करेगा और न्याय न्याय बोर्ड द्वारा दर्ज की गई आयु, न्याय न्याय अधिनियम, 2015 के प्रयोजन के लिए, उस व्यक्ति की वास्तविक आयु मानी जाएगी। इसलिए, न्यायधीश बोर्ड के समक्ष ऐसी कार्यवाही में आवश्यक साक्ष्य का स्तर, उस स्थिति की तुलना में अधिक होता है जब किसी संबंधित आपराधिक न्यायालय के समक्ष मुकदमे के दौरान किशोरता का दावा करने के लिए आवेदन दायर किया जाता है, जब

किसी न्यायालय द्वारा जांच की जाती है जिसके समक्ष अपराध के कमीशन के संबंध में मामला लंबित होता है (न्यायधीश अधिनियम, 2015 की धारा 9 देखें)।

जब किशोर होने का दावा उठाया जाता है, तो प्रारंभिक दायित्व को पूरा करने के लिए दावा उठाने वाले व्यक्ति पर न्यायालय को संतुष्ट करने का भार होता है। हालांकि, न्याय न्याय अधिनियम, 2000 के तहत बनाए गए न्याय न्याय नियम 2007 के नियम 12(3)(क)(i), (ii), और (iii) या न्याय न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 की उपधारा (2) में उल्लिखित दस्तावेज न्यायालय की प्रथम दृष्ट्या संतुष्टि के लिए पर्याप्त होंगे। उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर किशोर होने का अनुमान लगाया जा सकता है।

33.4. हालांकि, यह अनुमान किशोर होने की आयु का निर्णायक प्रमाण नहीं है और इसे विरोधी पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए विपरीत साक्ष्यों से खंडित किया जा सकता है।

33.5. न्यायालय द्वारा जांच की प्रक्रिया, न्याय न्याय बोर्ड के समक्ष विचाराधीन मामले में व्यक्ति की आयु को किशोर घोषित करने के समान नहीं है। जांच के मामले में, न्यायालय प्रथम दृष्टया निष्कर्ष दर्ज करता है, लेकिन जब 2015 अधिनियम की धारा 94 की उपधारा (2) के अनुसार आयु का निर्धारण किया जाता है, तो साक्ष्य के आधार पर घोषणा की जाती है। साथ ही, न्याय निर्णायक मंडल द्वारा दर्ज की गई आयु को उसके समक्ष प्रस्तुत व्यक्ति की वास्तविक आयु माना जाएगा। इस प्रकार, जांच में साक्ष्य का मानक उस मानक से भिन्न होता है जो किसी कार्यवाही में आवश्यक होता है, जहां किसी व्यक्ति की आयु का निर्धारण और घोषणा साक्ष्य के आधार पर की जानी होती है, जिसकी गहन जांच की जाती है और उसे तभी स्वीकार किया जाता है जब वह स्वीकार्य हो।

33.6. किसी व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए कोई अमूर्त सूत्र निर्धारित करना न तो व्यावहारिक है और न ही वांछनीय। यह अभिलेख में मौजूद सामग्री और प्रत्येक मामले में पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के मूल्यांकन के आधार पर होना चाहिए।

33.7. इस न्यायालय ने यह पाया है कि जब अभियुक्त की ओर से यह साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं कि वह किशोर था, तो अति- तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए।

33.8. यदि एक ही साक्ष्य पर दो मत संभव हों, तो सीमावर्ती मामलों में न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए है कि न्याय अधिनियम, 2015 का लाभ कानून से संघर्षरत किशोरों

को भी मिले, अभियुक्त को किशोर मानने के पक्ष में झुकना चाहिए। साथ ही, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्याय अधिनियम, 2015 का दुरुपयोग गंभीर अपराध करने के बाद सजा से बचने के लिए न किया जाए।

33.9. जब आयु का निर्धारण विद्यालय अभिलेखों जैसे साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अनुसार उन पर विचार करना आवश्यक है,क्योंकि आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में रखे गए किसी भी सार्वजनिक या आधिकारिक दस्तावेज की विश्वसनीयता निजी दस्तावेजों की तुलना में अधिक होती है।

33.10. कोई भी दस्तावेज जो सार्वजनिक दस्तावेजों के अनुरूप हो, जैसे कि मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, उसे न्यायालय या न्यायधीश बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा सार्वजनिक दस्तावेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 और अन्य प्रावधानों के अनुसार विश्वसनीय और प्रामाणिक हो।

33.11. अस्थि-निर्माण परीक्षण आयु निर्धारण का एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है और किसी व्यक्ति की आयु के संबंध में यांत्रिक राय केवल रेडियोलॉजिकल परीक्षण द्वारा प्राप्त चिकित्सा राय के आधार पर नहीं अपनाई जा सकती है।

ऐसा साक्ष्य निर्णायक साक्ष्य नहीं है, बल्कि न्यायधीश अधिनियम, 2015 की धारा 94(2) में उल्लिखित दस्तावेजों की अनुपस्थिति में विचार करने योग्य एक बहुत ही उपयोगी मार्गदर्शक कारक है।

*65. **ऋषिपाल सिंह सोलंकी** (उपरोक्त) अधिनियम, 2015 के अधीन है।*

66. **अधिनियम, 2013 की धारा 48 की तुलना अधिनियम, 2015 की धारा 94** से करने के उद्देश्य से, हम अधिनियम, 2015 की धारा 94 को भी नीचे पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं:

*"**94. आयु का अनुमान एवं निर्धारण.**– (1) जहाँ,*

समिति या बोर्ड को, इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत (साक्ष्य देने के उद्देश्य के अलावा) उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति की उपस्थिति के आधार पर यह स्पष्ट हो कि उक्त व्यक्ति एक बच्चा है, तो समिति या बोर्ड बच्चे की आयु को यथासंभव निकट बताते हुए ऐसा अवलोकन दर्ज करेगा और आयु की आगे की पुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना, धारा 14 या धारा 36 के तहत, जैसा भी मामला हो, जाँच आगे बढ़ाएगा।

(2) यदि समिति या बोर्ड को इस संबंध में संदेह के लिए उचित आधार हैं कि उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बच्चा है या नहीं, तो समिति या बोर्ड, जैसा भी मामला हो, आयु निर्धारण की प्रक्रिया को निम्नलिखित साक्ष्य प्राप्त करके संपन्न किया जाएगा:

(i) विद्यालय से जन्म प्रमाण पत्र, या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और इसके अनुपलब्ध होने पर;

(ii) निगम, नगर पालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र पर;

(iii) और केवल उपरोक्त (i) और (ii) के अभाव में, आयु का निर्धारण अस्थि-निर्माण परीक्षण या समिति या बोर्ड के आदेश पर किए गए किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण द्वारा किया जाएगा:

बशर्ते कि समिति या बोर्ड के आदेश पर किया गया ऐसा आयु निर्धारण परीक्षण आदेश की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।

(3) समिति या बोर्ड द्वारा किसी व्यक्ति की आयु के रूप में दर्ज की गई आयु, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, उस व्यक्ति की वास्तविक आयु मानी जाएगी।

67. इस न्यायालय ने मैट्रिक प्रमाण पत्र में दर्शाई गई जन्मतिथि का खंडन करने वाला कोई अन्य दस्तावेज न होने के तथ्य का हवाला देते हुए यह माना कि चिकित्सा साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें सत्र न्यायालय और किशोर न्याय बोर्ड के निर्णय की पुष्टि की गई थी। अतः, अभियुक्त के वकील द्वारा उद्धृत निर्णयों पर उपरोक्त अनुसार विचार किया जाना चाहिए और उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ये निर्णय अभियुक्त की किसी भी प्रकार से सहायता नहीं करते हैं। इसके विपरीत, ऊपर चर्चा किए गए सभी निर्णयों से यह निष्कर्ष निकलता है कि स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र आदि सहित दस्तावेजों की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी और इस संबंध में कोई कठोर नियम नहीं बनाया जा सकता है।

68. **पराग भाटी** (उपरोक्त) मामले में, **अबुजर हुसैन** मामले (उपरोक्त) और अन्य निर्णयों का हवाला देते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित कहा:

"34. यह निःसंदेह सत्य है कि यदि किशोर अभियुक्त के पक्ष में स्पष्ट और असंदिग्ध मामला है कि घटना की तिथि पर वह 18 वर्ष से कम आयु का नाबालिग था और दस्तावेजी साक्ष्य

कम से कम प्रथम दृष्टया इसे सिद्ध करते हैं, तो वह न्याय अधिनियम के तहत विशेष संरक्षण का हकदार होगा। लेकिन जब कोई अभियुक्त गंभीर और जघन्य अपराध करता है और उसके बाद नाबालिग होने की आड़ में वैधानिक शरण लेने का प्रयास करता है, तो अभियुक्त के किशोर होने या न होने के संबंध में लापरवाही या उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि न्यायालयों को न्याय प्रशासन के लिए सौंपी गई संस्था में आम आदमी के विश्वास की रक्षा के उद्देश्य से अपने कर्तव्यों का पालन करने का दायित्व सौंपा गया है।

न्याय प्रशासन के लिए सौंपी गई संस्था में आम आदमी का विश्वास बनाए रखना आवश्यक है।

35. न्याय अधिनियम से जुड़े परोपकारी विधान के सिद्धांत का लाभ केवल ऐसे मामलों में लागू होगा जिनमें अभियुक्त को नाबालिग माना जाता है, कम से कम प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर किशोर होने के कारण, गंभीर अपराध में शामिल आरोपी की उम्र के संबंध में दो संभावनाओं को देखते हुए, जिसे उसने सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया, जो उसकी परिपक्व मानसिकता को दर्शाता है न कि निर्दोषता को।

यह दर्शाता है कि उसकी किशोर होने की दलील कानून की पकड़ से बचने या उसे धोखा देने के लिए एक ढाल की तरह है, इसलिए उसे बचाव में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

(जोर दिया गया)

उपरोक्त कथन का सार यह है कि अधिनियम, 2000 का उद्देश्य गंभीर और जघन्य अपराधों के आरोपियों को शरण देना नहीं है।

69. इस न्यायालय ने **रामदेव चौहान उर्फ राज नाथ** (उपरोक्त) मामले सहित अपने कई निर्णयों में, जो हमारे द्वारा कही गई बात की पुष्टि करते हैं, निम्नलिखित टिप्पणी की है:

"यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता न तो बच्चा था और न ही किशोर न्याय अधिनियम या बाल अधिनियम के अर्थ में बच्चे की उम्र के आसपास था। यह सिद्ध हो चुका है कि अपराध करते समय वह बालिग था। इसमें कोई संदेह नहीं है, और न ही न्यायालय के मन में कोई उचित संदेह उत्पन्न होता है, जिससे आरोपी को कम सजा का लाभ मिल सके। यह सच है कि आरोपी ने अपनी उम्र को लेकर भ्रम पैदा करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने अपनी वास्तविक उम्र को छिपाने के लिए ऐसा किया, न कि हमारे मन में कोई संदेह पैदा करने के लिए। न्यायिक प्रणाली को काल्पनिक और मनगढ़ंत आधारों का सहारा लेकर, खासकर विशेष

अनुमति याचिका के चरण में, कुछ गवाहों के साक्ष्य में दिखाई देने वाले कमजोर वाक्यों का लाभ उठाकर बंधक नहीं बनाया जा सकता। कानून निर्णयों की अंतिमता पर जोर देता है और न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने से अधिक संबंधित है। न्यायालयों को न्याय प्रशासन के लिए सौंपी गई संस्था में आम आदमी के विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अपने कर्तव्यों का पालन करने का दायित्व सौंपा गया है। ऐसा कोई भी प्रयास जो व्यवस्था को कमजोर करता है और न्याय व्यवस्था में आम आदमी के विश्वास को डगमगाता है, उसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

(जोर दिया गया)

70. ***रामदेव चौहान उर्फ राज नाथ*** (उपरोक्त) मामले में उपर्युक्त टिप्पणियाँ निस्संदेह इस न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों द्वारा उस अभियुक्त को मृत्युदंड देने पर विचार करते समय दर्ज की गई थीं, जिसने स्वयं को नाबालिग होने का दावा किया था। फिर भी, उसमें व्यक्त विचार स्पष्ट रूप से उस मुद्दे को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जहाँ न्यायालय स्पष्ट रूप से कोई निष्कर्ष निकालने की स्थिति में नहीं है, जिसमें अभियुक्त या उसके अभिभावक द्वारा नाबालिग को उपलब्ध लाभों का दावा करके सहानुभूति प्राप्त करने और न्यायालय पर तथाकथित नाबालिग अभियुक्त के प्रति नरमी बरतने का दबाव बनाने का प्रयास किया गया हो, जबकि वास्तव में वह घटना के दिन बालिग था। (देखें ***ओम प्रकाश बनाम राजस्थान राज्य*** (2012) 5 एससीसी 201)।

71. **ओम प्रकाश** (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने अनुच्छेद 33, 34, 35, 36, 37 और 38 में निम्नलिखित टिप्पणी की:

"33. इसी प्रकार, यदि किसी आरोपी का आचरण या अपराध करने का तरीका और ढंग किसी दुष्ट और सुनियोजित इरादे को दर्शाता है, तो अपराध करने वाला आरोपी किसी निर्दोष बच्चे की तुलना में अधिक परिपक्व कौशल का संकेत देता है, अभियुक्त की आयु के समर्थन में विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में, यह दर्शाने वाले चिकित्सा साक्ष्य कि अभियुक्त बालिग था, को किशोर न्याय अधिनियम जैसे उदारवादी कानून के सिद्धांतों का सहारा लेकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह न्याय के मार्ग को बाधित करता है। किशोर न्याय अधिनियम के तहत वैधानिक संरक्षण निर्दोष नाबालिगों के लिए है, न कि उन परिपक्व अभियुक्तों के लिए जो नाबालिग होने का बहाना बनाकर अपने किए गए अपराध की सजा से खुद को बचाते हैं।

34. किशोर न्याय अधिनियम के तहत उदार कानून का लाभ स्पष्ट रूप से एक वास्तविक बाल आरोपी/ किशोर को संरक्षण प्रदान करेगा, जो अपनी नाबालिगता की दलील के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करके न्यायालय को इस दुविधा में नहीं डालता कि वह नाबालिग है या नहीं। लेकिन ऐसे साक्ष्यों के अभाव में, केवल कमजोर साक्ष्यों जैसे कि स्कूल प्रवेश रजिस्टर (जो सिद्ध नहीं हुआ है) या अनुमानों पर आधारित मौखिक साक्ष्य, जो और अधिक अस्पष्टता पैदा करते हैं, पर भरोसा करना आरोपी की आयु का आकलन करने के लिए चिकित्सा साक्ष्य की तुलना में उचित नहीं है।

35. चिकित्सा साक्ष्य की प्रासंगिकता और मूल्य पर विचार करते समय, डॉक्टर द्वारा अनुमानित आयु यद्यपि प्रमाण का ठोस आधार नहीं है क्योंकि यह केवल एक राय है, लेकिन अस्थि-निर्माण और रेडियोलॉजिकल परीक्षण जैसे वैज्ञानिक चिकित्सा परीक्षणों पर आधारित ऐसी राय को आरोपी किशोर की आयु निर्धारित करते समय सहायक साक्ष्य के रूप में माना जाना चाहिए।

*36. **रामदेव चौहान उर्फ राज नाथ बनाम असम राज्य** [(2001) 5 एससीसी 714: 2001 एससीसी (क्रिमिनल) 915] में, विद्वान न्यायाधीशों ने इस मुद्दे के निर्धारण के लिए एक अंतर्दृष्टि जोड़ी है, जब उन्होंने निम्नलिखित दर्ज किया: (एससीसी पृष्ठ 720 डी-ई)*

"निश्चित रूप से डॉक्टर द्वारा अनुमानित आयु प्रमाण का पुख्ता विकल्प नहीं है, क्योंकि यह केवल उनकी राय है। लेकिन किसी विशेषज्ञ की ऐसी राय को उस स्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जब न्यायालय किसी नागरिक की संभावित आयु का पता लगाने के लिए अनिश्चित स्थिति में हो, ताकि उसे संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया जा सके।

अन्य सभी मान्य साक्ष्यों के अभाव में, यदि ऐसी राय उसकी आयु सीमा के संबंध में एक उचित संभावना की ओर इशारा करती है, तो निश्चित रूप से इस पर विचार किया जाना चाहिए।"

(जोर दिया गया)

हालाँकि, स्थिति तब भिन्न होगी जब कथित किशोर की आयु छिपाने के लिए शैक्षणिक अभिलेखों को जानबूझकर रोके जाने का आरोप लगाया गया हो और अभियोजन पक्ष द्वारा चिकित्सा साक्ष्य की प्रामाणिकता को चुनौती दी गई हो। ऐसी स्थिति में, चिकित्सा साक्ष्य पर भरोसा किया जाना चाहिए या नहीं, यह स्पष्ट रूप से विवाद करने वाले पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के महत्व पर निर्भर करेगा।

37. *उपरोक्त चर्चा और मामले के प्रचलित तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित विश्लेषण के मद्देनजर, हमारा यह मत है कि प्रतिवादी 2 विजय कुमार और उनके पिता यह साबित करने में विफल रहे हैं कि अपराध के समय प्रतिवादी 2 नाबालिग था और इसलिए उसे किशोर न्याय अधिनियम का लाभ नहीं दिया जा सकता था। यह अधिनियम निस्संदेह एक उदार कानून है, लेकिन ऐसे आरोपी को इसका लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिसने अपनी वास्तविक उम्र छिपाने के प्रयास में नाबालिग होने का बहाना बनाया हो, ताकि निचली अदालतों के मन में संदेह पैदा हो सके, जिन्होंने केवल उदार कानून के सिद्धांत को अपनाकर उसे नाबालिग का लाभ देना उचित समझा, लेकिन इसके महत्वपूर्ण निहितार्थ को नजरअंदाज कर दिया कि यद्यपि किशोर न्याय अधिनियम स्वयं एक उदार कानून है, फिर भी इसके तहत संरक्षण ऐसे आरोपी को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता जो वास्तव में नाबालिग नहीं है, बल्कि केवल इसे एक सुरक्षात्मक छत्र या वैधानिक ढाल के रूप में उपयोग करके शरण चाहता है। हमें यह कहना होगा कि यदि साक्ष्य और अन्य रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री यह साबित करने में विफल रहती है कि अपराध करते समय आरोपी नाबालिग था, तो इसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए।*

38. *किशोर न्याय अधिनियम, जिसका उद्देश्य निश्चित रूप से बाल अभियुक्तों के साथ देखभाल और संवेदनशीलता से व्यवहार करना और उन्हें समाज की मुख्यधारा में सुधरने और समायोजित होने का अवसर प्रदान करना है, उसे जघन्य अपराधों के मुकदमे और उपचार के दौरान न्याय की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए एक चाल के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसे स्पष्ट रूप से न्याय व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास माना जाएगा और इसलिए इसे प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता।*

72. अतः, यह निःसंदेह सत्य है कि यदि किशोर अभियुक्त के पक्ष में यह स्पष्ट और असंदिग्ध मामला हो कि घटना की तिथि को वह नाबालिग था और दस्तावेजी साक्ष्य कम से कम प्रथम दृष्टया इसे सिद्ध करते हों, तो वह किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत विशेष संरक्षण का हकदार होगा। यद्यपि, जब कोई अभियुक्त इस मामले की तरह जघन्य और गंभीर अपराध

करता है और उसके बाद नाबालिग होने की आड़ में वैधानिक सुरक्षा का सहारा लेने का प्रयास करता है, तो अभियुक्त के किशोर होने या न होने के संबंध में लापरवाही या उपेक्षापूर्ण रवैया स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि न्यायालयों को न्याय प्रशासन के लिए सौंपी गई संस्था में आम आदमी के विश्वास की रक्षा करने के उद्देश्य से अपने कर्तव्यों का पालन करने का दायित्व सौंपा गया है। जैसा कि इस न्यायालय ने पराग भाटी (उपरोक्त) मामले में कहा है, किशोर न्याय अधिनियम से जुड़े उदार विधान के सिद्धांत का लाभ केवल उन्हीं मामलों में दिया जा सकता है, जिनमें आरोपी को कम से कम प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर किशोर माना जाता है, जो उसकी नाबालिगता के संबंध में विश्वास दिलाता हो। गंभीर अपराध में शामिल आरोपी की उम्र के संबंध में दो दृष्टिकोणों की संभावना का लाभ, जिसे उसने कथित तौर पर अंजाम दिया है और जिसे उसने सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया है, जो उसकी निर्दोषता के बजाय उसकी परिपक्व मानसिकता को दर्शाता है, यह दर्शाता है कि उसकी किशोरता की दलील कानून से बचने या उसे धोखा देने के लिए एक ढाल की तरह है।

73. अभिलेख में मौजूद सामग्री से यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादी के पिता ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1956 की धारा 19(3) एवं नियमों की धारा 19(3) के अंतर्गत आवेदन करते समय हीरा नगर नगर समिति के कार्यकारी अधिकारी के समक्ष यह घोषणा की थी कि हीरा नगर की चिकित्सा समिति उनके तीन बच्चों, जिनमें प्रतिवादी भी शामिल है, के जन्म को दर्ज करने में विफल रही है। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने अधिनियम, 1956 की धारा 19(3) के अंतर्गत जन्म तिथि एवं स्थान के संबंध में संबंधित प्राधिकारी से आदेश मांगा था।

हालांकि, हीरा नगर के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी द्वारा जम्मू के पुलिस अधीक्षक को दिनांक 15.03.2018 को लिखे गए पत्र में यह कहा गया है कि श्रीमती तृप्ता देवी,पत्नी ओम प्रकाश के नाम से 23.10.2002 को नगर अस्पताल में कोई प्रसव नहीं हुआ था।

इससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

74. पाँच योग्य चिकित्सकों की एक टीम द्वारा दिए गए अंतिम मत की विश्वसनीयता को नज़रअंदाज़ करने, अनदेखा करने या संदेह करने का कोई अच्छा कारण नहीं है। इस टीम में एक चिकित्सक शरीर क्रिया विज्ञान विभाग से, एक शरीर रचना विज्ञान विभाग से, एक मुख निदान विभाग से, एक फोरेंसिक चिकित्सा विभाग से और एक रेडियो निदान विभाग से था। इन सभी चिकित्सकों ने एक ही शब्द में कहा कि शारीरिक, दंत और रेडियोलॉजिकल परीक्षण

के आधार पर प्रतिवादी की अनुमानित आयु 19 से 23 वर्ष के बीच निर्धारित की जा सकती है।

75. हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि आयु निर्धारण के लिए बेहतर तकनीकें उपलब्ध हैं और विश्व भर में इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए,अमेरिका का आव्रजन विभाग उम्र निर्धारण के लिए 'अक्ल दाढ़' तकनीक का इस्तेमाल करता है। इस तकनीक में डॉक्टर तीसरी दाढ़ की जांच करते हैं, जो आमतौर पर 17 से 25 वर्ष की आयु के बीच निकलती है। इस तकनीक में औसत त्रुटि अन्य किसी भी हड्डी के अस्थिभवन की तुलना में काफी कम होती है। एक अन्य तकनीक 'एपीजेनेटिक क्लॉक' तकनीक है। एपीजेनेटिक क्लॉक एक डीएनए घड़ी है जो किसी ऊतक या अंग की आयु का अनुमान लगाने के लिए डीएनए मिथाइलेशन स्तर को मापती है। इस तकनीक में औसत त्रुटि को चार सप्ताह से भी कम किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य यह बताना है कि ऐसी तकनीकों को हमारे देश में भी लागू किया जाना चाहिए। (संदर्भ: शामिन टी, आयु निर्धारण: दंत चिकित्सा दृष्टिकोण, जर्नल ऑफ पंजाब एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड

टॉक्सिकोलॉजी, खंड 6 अंक 1. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरीयल नंबर-0972-5687)

76. जैसा कि इस न्यायालय ने ***रामदेव चौहान उर्फ राज नाथ*** (उपरोक्त) मामले में कहा है, चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा आयु का अनुमान प्रमाण का वैधानिक विकल्प नहीं हो सकता और यह केवल एक राय है, लेकिन जब न्यायालय स्वयं संवैधानिक संरक्षण का दावा करने वाले नागरिक की आयु के संबंध में संदेह में हो, तो विशेषज्ञ की ऐसी राय को नजरअंदाज या खारिज नहीं किया जाना चाहिए। अन्य सभी स्वीकार्य सामग्रियों के अभाव में, यदि विशेषज्ञ की ऐसी राय उसकी आयु सीमा के संबंध में एक उचित संभावना की ओर इशारा करती है, तो न्यायालय को न्याय के हित में इस पर विचार करना चाहिए। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अपीलकर्ता राज्य पर जानबूझकर आवश्यक अभिलेखों को केवल कथित किशोर की आयु को छिपाने या छुपाने के उद्देश्य से रोके रखने का आरोप लगाया गया हो और अभियोजन पक्ष के कहने पर चिकित्सा साक्ष्य की प्रामाणिकता को चुनौती दी गई हो। यदि ऐसा होता तो चिकित्सा साक्ष्य पर भरोसा किया जाना चाहिए या नहीं, यह स्पष्ट रूप से विवाद करने वाले पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य के मूल्य पर निर्भर करता।

77. यह ध्यान देने योग्य है कि पांच चिकित्सा विशेषज्ञों से गठित विशेष चिकित्सा बोर्ड द्वारा तैयार की गई चिकित्सा रिपोर्ट की विश्वसनीयता के संबंध में प्रतिवादी अभियुक्त की ओर से

कुछ खास नहीं कहा गया है। पुनरावृत्ति से बचने के लिए, उनका एकमात्र तर्क यह है कि चिकित्सा रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया जाए क्योंकि रिकॉर्ड में मौजूद विभिन्न दस्तावेजों में जन्मतिथि का प्रमाण मौजूद है। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि जन्मतिथि को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज किसी भी प्रकार से विश्वासयोग्य नहीं हैं और न्याय के हित में विशेष चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट पर ही निर्भर रहना एकमात्र विकल्प है।

78. मामले के समग्र अवलोकन से हम आश्वस्त हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य न्यायिक न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करने वाला आदेश कानून की दृष्टि से मान्य नहीं है।

79. इस मामले को समाप्त करने से पहले, हम यह कहना चाहेंगे कि भारत में किशोर अपराध की बढ़ती दर चिंता का विषय है और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे देश में एक विचारधारा प्रचलित है जो दृढ़ता से मानती है कि अपराध चाहे कितना भी जघन्य क्यों न हो, चाहे वह एकल बलात्कार हो, सामूहिक बलात्कार हो, मादक पदार्थों की तस्करी हो या हत्या हो, लेकिन यदि आरोपी किशोर है, तो उसके साथ केवल एक ही बात को ध्यान में रखते हुए व्यवहार किया जाना चाहिए, अर्थात् सुधार का लक्ष्य। जिस विचारधारा की हम बात कर रहे हैं, वह मानती है कि सुधार का लक्ष्य आदर्श है। जिस तरह से किशोरों द्वारा समय-समय पर क्रूर और जघन्य अपराध किए गए हैं और अभी भी किए जा रहे हैं, उससे हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या अधिनियम, 2015 अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पाया है। हमें यह आभास होने लगा है कि सुधार के नाम पर किशोरों के साथ जिस नरमी से पेश आया जा रहा है, उससे वे ऐसे जघन्य अपराधों में लिप्त होने के लिए और अधिक प्रोत्साहित हो रहे हैं। सरकार को यह विचार करना चाहिए कि क्या उसका 2015 का अधिनियम प्रभावी साबित हुआ है या इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इस मामले में अभी भी कुछ करने की आवश्यकता है।

परिणामस्वरूप, यह अपील सफल होती है और इसे स्वीकार किया जाता है।

मुख्य न्यायिक न्यायाधीश, कठुआ और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश रद्द किया जाता है। यह माना जाता है कि अपराध के समय प्रतिवादी अभियुक्त नाबालिग नहीं था और उस पर अन्य सह- आरोपियों की तरह ही कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाना चाहिए। कानून को अपना काम करने दें।

81. यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रतिवादी अभियुक्त का दोष या निर्दोषता मुकदमे के समय अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही

निर्धारित की जाएगी। इस निर्णय में की गई सभी टिप्पणियाँ केवल नाबालिग होने के मुद्दे पर निर्णय लेने के उद्देश्य से हैं।

82. कोई भी लंबित आवेदन को निपटा दिया गया है।

देविका गुजराल अपील स्वीकार की गई।

(सहायता: शुभांशु दास, एलसीआरए)

यह अनुवाद (सुधीर), पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है।